@saahassamachar @saahassamachar @saahassamachar

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

राष्ट्रीय संस्करण

साहस समाचार

निष्पक्ष, निर्भीक, बेबाक

नई दिल्ली, बुधवार, 17 दिसंबर 2025, वर्ष-1, अंक-54, पृष्ठ-8, मूल्य-2 रुपए RNI No-DLHIN/25/A2841 www.saahassamachar.in

समीरा रेड्डी ने शेयर की 'बनाना स्टेम' जूस की रेसिपी, बताया डिटॉक्स का प्राकृतिक तरीका... पेज-8

जी राम जी बिल पर संसद में संग्राम, महात्मा गांधी का नाम हटाने पर भड़का विपक्ष

नई दिल्ली, एजेंसी।

सरकार ने विपक्ष के तीखे विरोध के बीच मंगलवार को लोकसभा में 'विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025' पेश किया, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर लाया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच 'विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)' (विकसित भारत-जी राम जी) विधेयक, 2025' पेश करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दी।

विपक्षी सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना उनका अपमान है। उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक को वापस लिया जाए या फिर संसदीय समिति के पास भेजा जाए। चौहान ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं। उनका कहना था कि मोदी सरकार महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर आधारित कई योजनाएं चला रही है।

उन्होंने सवाल किया, कांग्रेस की सरकार ने भी जवाहर रोजगार योजना का नाम बदला था तो क्या यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपमान था? चौहान ने कहा कि सरकार ने मनरेगा पर 8.53 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

उन्होंने बताया, हम इस विधेयक में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। यह कोई कोरी गारंटी नहीं है, बल्कि 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि महात्मा

गांधी ने भी रामराज्य की कल्पना की थी और उनके आखिरी शब्द भी 'हे राम' थे। चौहान ने कहा कि इस विधेयक से गांवों का संपूर्ण विकास होगा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाद्रा ने विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि इससे रोजगार का कानूनी अधिकार कमजोर हो रहा है।

उन्होंने कहा, मनरेगा में 90 प्रतिशत अनुदान केंद्र से आता था, लेकिन इस विधेयक में ज्यादातर प्रदेशों में अब 60 प्रतिशत अनुदान ही आएगा। इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार पड़ेगा। ये उन प्रदेशों को और प्रभावित करेगा जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही केंद्र की जीएसटी के बकाया का इंतजार कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटाई जा रही है। केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य ने कहा, यह विधेयक काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 करने की बात करता है, लेकिन इसमें मज़दूरी बढ़ाने की कोई बात नहीं है।

उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हर योजना का नाम बदलने की सरकार की सनक हमें समझ नहीं आती। जब-जब ऐसा किया जाता है, तब केंद्र को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि बिना चर्चा और सदन की सलाह लिए इस विधेयक को पारित नहीं किया जाना चाहिए।

उनका कहना था, यह विधेयक वापस लिया जाना चाहिए, इसके बदले एक नया विधेयक लाया जाना चाहिए। गहन अध्ययन और व्यापक चर्चा के लिए कम से कम यह विधेयक संसद की स्थायी समिति को भेजा जाए।

उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, कोई विधेयक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पारित होना चाहिए।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी विधेयक के शीर्षक में महात्मा गांधी का नाम नहीं होने पर विरोध जताया।

उन्होंने कहा, महात्मा गांधी का राम राज्य का दृष्टिकोण कभी भी पूरी तरह से राजनीतिक प्रोजेक्ट नहीं था। यह एक सामाजिक-आर्थिक ब्लूप्रिंट था जो गांवों को मज़बूत बनाने पर आधारित था और ग्राम स्वराज में उनका अटूट विश्वास उस दृष्टिकोण का मुख्य हिस्सा था।

थरूर ने दावा किया कि मूल अधिनियम में राष्ट्रपिता का नाम रखकर इस गहरे जुड़ाव को स्वीकारा गया था कि सच्ची रोज़गार गारंटी और तरक्की ज़मीनी स्तर से ही होनी चाहिए, जो सबसे आखिरी व्यक्ति को सबसे पहले रखने के उनके सिद्धांत को दिखाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि महात्मा गांधी का नाम हटाना विधेयक से उसके नैतिक आधार और ऐतिहासिक वैधता को छीनना है।

सार समाचार

दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान परिचालन प्रभावित, 131 उड़ानें रद्द

मुंबई,एजेंसी। दिल्ली हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के कारण उड़ान परिचालन बाधित हुआ जिससे विमानन कंपनियों की 131 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा, खराब दृश्यता के कारण दिल्ली हवाई अड्डे से अब तक 52 प्रस्थान और 79 आगमन उड़ान रद्द की जा चुकी हैं। भारत के उत्तरी भागों में घने कोहरे के कारण दृश्यता कम है, जिससे पूरे नेटवर्क में उड़ान कार्यक्रम पर व्यापक प्रभाव पड़ने की आशंका है। उत्तरी भागों में जिनमें एअर इंडिया का प्राथमिक केंद्र दिल्ली भी शामिल है।

जब तक शीर्ष नेतृत्व चाहेगा मैं मुख्यमंत्री पद पर कायम रहूंगा: सिद्धरमैया

बेलगावी,एजेंसी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मंगलवार को फिर कहा कि जब तक कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व चाहेगा वह मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी को पांच साल तक शासन के लिए जनादेश मिला है और वह (पार्टी) 2028 के विधानसभा चुनाव के बाद भी सत्ता में वापसी करेगी। सिद्धरमैया ने विधानसभा में कहा, ₹मैं यह बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। हमारे पास शीर्ष नेतृत्व है। हम उनके फैसले का पालन करते हैं। शीर्ष नेतृत्व जो कहे, वही अंतिम होता है।

लूथरा बंधु थाईलैंड से प्रत्यर्पित, गिरफ्तार

नई दिल्ली,एजेंसी। गोवा के 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब के सह-मालिकों गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को थाईलैंड से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद मंगलवार को दिल्ली पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें दो दिन की 'ट्रांजिट रिमांड' पर रखा गया है ताकि उन्हें गोवा की अदालत में पेश किया जा सके। नाइटक्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तरी गोवा के अरपोरा में 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब में आग लगने के 10 दिन बाद, दोनों भाई इंडिगो की उड़ान से दिल्ली लाए गए और उन्हें आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए तुरंत अधिकारियों के हवाले कर दिया गया। गोवा पुलिस के मुताबिक, लूथरा बंधुओं को बुधवार को पूर्वाह्न 11 बजे दिल्ली से गोवा लाया जाएगा। गौरव और सौरभ अपने नाइटक्लब में आग लगने के कुछ घंटों बाद फुकेत भाग गए थे। कड़ी सुरक्षा के बीच, गौरव और सौरभ को पटियाला हाउस अदालत में न्यायिक मजिस्ट्रेट ट्विंकल चावला के समक्ष पेश किया गया।

हम भारत और इथियोपिया के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जा रहे हैं

भारत-इथियोपिया के रिश्ते हुए और मजबूत: पीएम मोदी

अदीस अबाबा, एजेंसी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ. अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय वार्ता की तथा इस दौरान भारत और इथियोपिया ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति जताई।

प्रधानमंत्री मोदी तीन देशों की चार दिवसीय यात्रा के दूसरे चरण के तहत मंगलवार को इथियोपिया पहुंचे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ. अबी अहमद अली ने अदीस अबाबा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मोदी का स्वागत किया। वह मोदी को अपनी गाड़ी में बैठाकर होटल तक भी ले गए। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कहा, हम भारत और इथियोपिया के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जा रहे हैं। यह कदम हमारे संबंधों को नयी ऊर्जा, नयी गति और नयी गहराई प्रदान करेगा। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री अली को धन्यवाद दिया। मोदी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ इस संघर्ष में मित्र देशों का समर्थन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज हमें अर्थव्यवस्था, नवाचार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, स्वास्थ्य और बहुपक्षीय सहयोग जैसे हमारे सहयोग के प्रमुख पहलुओं पर विचार-विमर्श करने का अवसर मिला। मुझे खुशी है कि आज हमने भारत में इथियोपिया

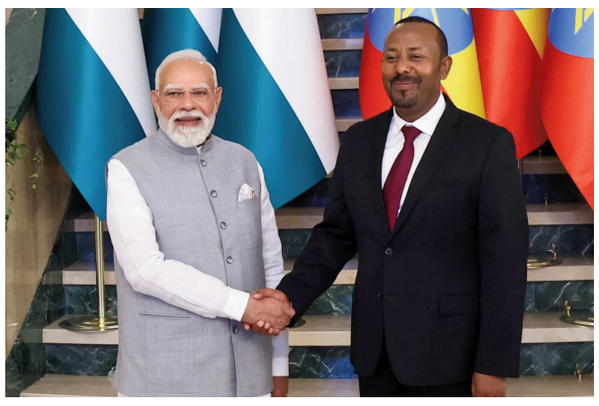

के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति को दोगुना करने का निर्णय लिया है।

मोदी ने कहा कि भारत और इथियोपिया के बीच हजारों वर्षों से संपर्क, संवाद और आदान-प्रदान होता रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भाषा और परंपराओं से समृद्ध ये दोनों देश विविधता में एकता के प्रतीक हैं। मोदी ने कहा, दोनों देश लोकतांत्रिक शक्तियां हैं जो शांति और मानवता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम 'ग्लोबल साउथ' के सहयात्री और साझेदार हैं। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हालांकि यह उनकी पहली यात्रा है, फिर भी उन्हें अपनेपन और आत्मीयता का गहरा अहसास हुआ, जो दोनों देशों के बीच हजारों वर्षों के संबंधों को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री अली ने कहा कि दोनों देश व्यापार, कूटनीति, शिक्षा, संस्कृति और यहां तक कि खान-पान और परंपराओं के माध्यम से हजारों वर्षों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, ये संबंध हमारे लोगों के बीच गहरी मित्रता, सहयोग और आपसी सम्मान को आकार देते रहते हैं। इससे पहले, अली ने मोदी को विज्ञान संग्रहालय और मैत्री पार्क का भ्रमण करवाया, जो यात्रा कार्यक्रम में शामिल नहीं था। उन्होंने मोदी को इथियोपियाई कॉफी की अलग-अलग किस्मों के बारे में जानकारी भी दी। सूत्रों ने कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अली का यह विशिष्ट व्यवहार मोदी के प्रति उनके उल्लेखनीय सम्मान को दर्शाता है। मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "कुछ देर पहले अदीस अबाबा पहुंचा। प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया, जिससे मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इथियोपिया एक महान इतिहास और जीवंत संस्कृति वाला राष्ट्र है।

पीएम मोदी को मिला इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान

अदीस अबाबा, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मंगलवार को उनके इथियोपियाई समकक्ष अबी अहमद अली ने इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान 'द ग्रेट ऑनर निशां ऑफ इथियोपिया' से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान मंगलवार को अदीस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया।

विदेश मंत्रालय ने नयी दिल्ली में जारी एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को भारत-इथियोपिया साझेदारी को मजबूत करने में उनके असाधारण योगदान और वैश्विक राजनेता के रूप में उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए यह सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले वैश्विक राष्ट्राध्यक्ष/सरकार प्रमुख हैं।

मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, मुझे 'द ग्रेट ऑनर निशां ऑफ इथियोपिया' से सम्मानित किए जाने पर गर्व है। मैं इसे भारत के 140 करोड़ लोगों को समर्पित करता हूं।

बयान के अनुसार, इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक से यह पुरस्कार स्वीकार करना उनके लिए सम्मान की बात है और उन्होंने इसे अत्यंत विनम्रता एवं कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया।

बंगाल में एसआईआर के तहत मतदाता सूची से 58 लाख नाम हटाए गए

कोलकाता, एजेंसी।

पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मसौदा सूचियों से 58 लाख से अधिक नाम हटा दिए गए हैं। इससे विभिन्न जिलों, सीमावर्ती क्षेत्रों और 'हाई-प्रोफाइल' निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की स्थिति में बदलाव आया है। पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में ये कई दशकों में सबसे बड़ा बदलाव है और 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले नयी सियासी हलचल पैदा हो गई है।

यहां मंगलवार को प्रकाशित मतदाता सूची के मसौदे के अनुसार, राज्य में मतदाताओं की संख्या लगभग 7.66 करोड़ थी जो घटकर 7.08 करोड़ के आस-पास रह गई है। मृत्यु और स्थायी पलायन से

लेकर नामों के दोहराव तथा गणना प्रपत्र जमा न करने जैसे विभिन्न कारणों से मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रक्रिया अस्थायी है और सुनवाई के अधीन है। इस बदलाव का असर सबसे अधिक उत्तर बंगाल में दिख रहा है, जहां सभी सात जिलों में बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं।

निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने संकेत दिया है कि सिलीगुड़ी से लगभग 31,181 नाम हटाए जा सकते हैं, जबकि कलिम्पोंग में लगभग 17,321 नाम हटाए जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार, जलपाईगुड़ी सबसे अधिक प्रभावित जिलों में से एक है।

डबग्राम-फुलबारी सीट पर लगभग 3.25 लाख मतदाता हैं और यहां से 38,395 नाम हटाए जाने हैं, जिनमें 12 हजार से अधिक मृत घोषित किए गए नाम और लगभग 19 हजार लापता नाम शामिल हैं। माल सीट से 21,127 मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं, जबकि जलपाईगुड़ी सदर, राजगंज, नागराकाटा और धूपगुड़ी में हजारोंक की संख्या में मतदाताओं का नाम हटाए जाने की सूचना है।

केन्द्र ने 20 राज्यों के लिए 507 करोड़ रुपये मंजूर किये

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने 20 राज्यों के लिए पंचायती राज संस्थानों में समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पहल को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय परियोजना के लिए 507.37 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। मंत्रालय ने बताया कि यह पहल पंचायती राज मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सहयोग के आधार पर की गई है। सरकार ने समाज को किसी भी आपदा से निपटने के लिए कवच प्रदान करने के उद्देश्य से 2021 में राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष की शुरुआत की और अब इस पहल को पंचायत स्तर तक बढ़ा दिया गया है। सरकार किसी भी आपदा का आत्मविश्वास के साथ सामना करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सशक्त बनाने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।

नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल गांधी को राहत

नई दिल्ली,एजेंसी।

कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पांच अन्य लोगों को राहत देते हुए, दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए धनशोधन के आरोपों पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा इस मामले में दाखिल आरोप-पत्र एक निजी व्यक्ति की शिकायत पर की गई जांच पर आधारित है, न कि किसी मूल अपराध से संबंधित प्राथमिकी पर। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि कानून के तहत इस पर संज्ञान लेना स्वीकार्य नहीं है।

न्यायाधीश ने कहा कि ईडी की शिकायत निजी व्यक्ति सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत की जांच पर आधारित थी, न कि किसी मूल अपराध की प्राथमिकी पर। न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा पहले ही प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है इसलिए ऐसे में गुण-दोष के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय के तर्कों पर विचार करना अभी जल्दबाजी होगी। अदालत ने कहा अन्य तर्क संभवतः भविष्य में फिर से सामने आएंगे। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि जांच एजेंसी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समेत विधि विशेषज्ञों से राय लेने के बाद अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर कर सकती है।

भारत-चीन के बीच शिपकी-ला दर्रे से फिर शुरू होगा व्यापार

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत और चीन शिपकी-ला दर्रे के माध्यम से सीमा-पार व्यापार फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। विदेश मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित शिपकी-ला के माध्यम से व्यापार को फिर से शुरू करने के लिए औपचारिक मंजूरी दे दी है। अगले साल जून से इस व्यापार के शुरू होने की उम्मीद है।

इस कदम को दोनों एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक महत्वपूर्ण विश्वास-निर्माण उपाय के रूप में देखा जा रहा है, जिनकी लंबी और संवेदनशील सीमा 20वीं सदी के मध्य से व्यावसायिक आदान-प्रदान के लिए अधिकांश बंद ही रही है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद, किन्नौर जिला प्रशासन ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं।

ग्रीन ने स्टार्क को पीछे छोड़ते हुए आईपीएल नीलामी में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया

केकेआर ने ग्रीन को रिकॉर्ड 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा

अबू धाबी, एजेंसी।

कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के खिलाड़ियों की नीलामी में मंगलवार को यहां ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज हरफनमौला ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन के लिए रिकॉर्ड 25.20 करोड़ रुपये और श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना के लिए 18 करोड़ रुपये खर्च किए। पृथ्वी साव और सरफराज खान जैसे भारतीय बल्लेबाजों को अच्छी लय में होने के बावजूद इस नीलामी में कोई खरीदार नहीं मिला।

ग्रीन ने अपने हमवतन मिशेल स्टार्क (24.75 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ते हुए आईपीएल नीलामी में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया।

केकेआर और चेन्नई सुपर

किंग्स के बीच उनके लिए कड़ी बोली लगी, जिसके अंत में चेन्नई की फ्रेंचाइजी पिछड़ गयी।

केकेआर ने इसके बाद वेंकटेश अय्यर को हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस हरफनमौला को सात करोड़ रुपये की बोली के साथ अपनी से जोड़ा। तीन बार की इस चैंपियन ने श्रीलंका के तेज गेंदबाज पथिराना को खरीदने की होड़ में तब प्रवेश किया जब दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स ने शुरुआती बोली के बार पीछे हटने का फैसला किया। दो करोड़ रुपये की आधार मूल्य के साथ इस नीलामी में शामिल होने वाले पथिराना आईपीएल में बिकने वाले सबसे महंगे श्रीलंकाई खिलाड़ी बन गए। विदेशी खिलाड़ियों के लिए नीलामी के नियमों के अनुसार हालांकि शेष राशि बीसीसीआई के खिलाड़ी विकास कार्यक्रम में जाएगी। ऐसे में इस सत्र के लिए उनका वेतन 18 करोड़ रुपये (19 लाख अमेरिकी डॉलर) ही रहेगा। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व करने वाले पथिराना को हालांकि पूरी रकम मिलेगी क्योंकि वह वेतन सीमा के अंदर है।

ग्रीन इससे पहले मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल चुके हैं। उन्होंने आईपीएल के 29 मैचों में 707 रन बनाने के अलावा 16 विकेट भी चटकाए है।

साव हालांकि घरेलू क्रिकेट में शानदार लय में होने के बावजूद किसी फ्रेंचाइजी को प्रभावित करने में नाकाम रहे। यह हाल सरफराज का भी रहा जिन्होंने मंगलवार को मुंबई के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैच में 22 गेंदों में 73 रन बनाए।

दक्षिण अफ्रीका के आक्रामक बल्लेबाज डेविड मिलर को दिल्ली कैपिटल्स ने उनके आधार मूल्य दो करोड़ रुपये में खरीदा जबकि न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज डेवोन कॉन्वे (आधार मूल्य दो करोड़ रुपये) नीलामी में नहीं बिके।

दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी सलामी बल्लेबाज एवं विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक एक करोड़ रुपये के आधार मूल्य पर अपनी पुरानी टीम मुंबई इंडियंस में वापस लौटे।

यमुना एक्सप्रेसवे पर कई वाहन टकराए, 13 लोगों की मौत

मथुरा, एजेंसी।

मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के कई बसों व तीन अन्य गाड़ियों के आपस में टकराने के बाद कई वाहनों में लगी आग में झुलसने से 13 लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी।अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में करीब 95 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। इस बीच जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी (एडीएम) के नेतृत्व में चार सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है, जिसे दो दिनों के भीतर तफ्तीश पूरी कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिये गये हैं।

यमुना एक्सप्रेस-वे के आगरा-नोएडा साइड पर मंगलवार तड़के हुए हादसे की जांच के लिए मथुरा के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अमरेश कुमार को नामित किया है। उन्होंने बताया कि यह हादसा तड़के करीब साढ़े चार बजे यमुना एक्सप्रेसवे पर बलदेव थाना क्षेत्र में तब हुआ जब घने कोहरे में आठ बस और तीन छोटे वाहन आपस में टकरा गए। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) श्लोक कुमार ने कहा, आगरा से नोएडा की ओर जा रहे वाहनों की आपस में टक्कर हो गई। उन्होंने बताया कि संभवतः कोहरा होने से कम दृश्यता के कारण यह हादसा हुआ।

10 करोड़ की अवैध शराब 24 घंटे भी गोदाम में नहीं टिक पाई

आबकारी विभाग के सूत्रों के अनुसार, शराब की खेप ठेके पर पहुंचते ही विभाग के उच्चाधिकारियों के पास इसकी शिकायत पहुंच गई थी।

गुरुग्राम,एजेंसी।

आबकारी विभाग द्वारा पकड़ी गई दस करोड़ की अवैध विदेशी शराब ठेके पर ठेकेदार 24 घंटे भी नहीं रोक पाया। ठेकेदार आठ दिसंबर की रात को ही दो से तीन वाहनों में इस अवैध विदेशी शराब को ठेके पर लेकर आया था। अगले दिन नौ दिसंबर को विभाग के उच्च अधिकारियों के पास इस अवैध शराब की सूचना और शिकायत पहुंच गई थी। इसके बाद विभाग के अधिकारियों ने बिना किसी देरी के दोपहर दो बजे ही सिग्नेचर टॉवर स्थित दी ठेका की वाइन शॉप पर छापेमारी कर दी थी। आबकारी विभाग के सूत्रों के अनुसार, शराब की खेप ठेके पर पहुंचते ही विभाग के उच्चाधिकारियों के पास इसकी शिकायत पहुंच गई थी।

शिकायत की गंभीरता को देखते हुए, विभाग ने बिना किसी देरी के तुरंत टीमों का गठन किया और संबंधित शराब ठेके पर छापेमारी शुरू कर दी। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि मोटा मुनाफा कमाने के लिए ठेकेदार ने पहली बार एक साथ बड़ी खेप में कई गाड़ियों से शराब मंगवाई थी। ठेकेदार ने ठेके के अंदर ही एक सीक्रेट कमरा बना रखा था, जिसे किसी नहीं देखने वाला कमरा कहा जा रहा है। इस कमरे में अवैध विदेशी शराब को छिपाकर रखा गया था और डिमांड आने के बाद ही कमरे से बाहर निकालकर बेची जाती थी।

यहीं कारण था कि अवैध विदेशी शराब को छिपाकर ठेकेदार आसानी से बेच रहा था, लेकिन आबकारी विभाग को इस सीक्रेट कमरे की सूचना पहले नहीं थी। एक शराब कारोबारी ने ही विभाग को इसकी गुप्त सूचना दी थी। इसको लेकर उसने अधिकारियों को शिकायत भी दी हुई है। जांच में कस्टम विभाग में सेंधमारी का खुलासा आबकारी विभाग की गहन जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि जब्त की गई यह अवैध विदेशी शराब कस्टम विभाग में सेंध लगाकर लाई गई थी, यानी इस पर जरूरी कस्टम ड्यूटी और टैक्स का भुगतान नहीं किया गया था।

इस तरह की अवैध गतिविधि से राज्य के राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा था। आबकारी विभाग ने शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई की, जिसके चलते ठेकेदार का बड़ा नेटवर्क ध्वस्त हुआ। इसके अलावा विभाग की जांच में खुलासा हुआ है कोई अभिषेक दहिया सप्लायर है जो शहर के शराब के ठेकों में यह अवैध विदेशी शराब सप्लाई करता है। इस सप्लायर की तालाश भी पुलिस ने शुरू कर दी है। कार्रवाई करने वाले निरीक्षक को ही किया निलंबित इस पूरी कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम देने में शामिल रहे आबकारी निरीक्षक को विभाग ने उसी दिन ही निलंबित कर दिया था, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

जबकि निरीक्षक की तरफ से इस कार्रवाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि विभाग ने यह कार्रवाई आंतरिक दबाव या अन्य कारणों से की है। हालांकि, इस निलंबन के कारणों की विस्तृत जांच अभी बाकी है। इस घटना ने एक बार फिर शहर में अवैध शराब के कारोबार के बढ़ते दायरे और उसके पीछे काम करने वाले बड़े सिंडिकेट की तरफ इशारा किया है। विभाग अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रहा है।

नशे की हालत में युवक ने नहर में लगाई छलांग

फरीदाबाद,एजेंसी।

फरीदाबाद में एत्मादपुर पुल के पास आगरा नहर में देर रात एक युवक ने नशे की हालत में छलांग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की तलाश शुरू की गई, लेकिन अंधेरा अधिक होने के कारण रात में उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। नहर में कूदने वाले युवक की पहचान 23 वर्षीय नवनीत के रूप में हुई है। उसके पिता उमेश सिंह ने बताया कि सोमवार रात करीब साढ़े दस बजे उनके बड़े बेटे ने फोन कर सूचना दी कि नवनीत एत्मादपुर पुल के पास नहर में कूद गया है। सूचना मिलते ही वे अपने बड़े बेटे के साथ मौके पर पहुंचे और पुल के आसपास नहर में तलाश की, लेकिन नवनीत नहीं मिला।

इसके बाद आपातकालीन नंबर पर सूचना दी गई, जिस पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने परिजनों के साथ मिलकर युवक को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन अंधेरा होने के कारण सफलता नहीं मिल सकी। मंगलवार सुबह पल्ला थाना और खेड़ी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने आपदा बचाव दल के साथ मिलकर दोबारा तलाश अभियान शुरू किया। करीब तीन घंटे तक नहर में खोजबीन की गई और लगभग तीन किलोमीटर क्षेत्र को खंगाला गया, लेकिन युवक का अब तक कोई पता नहीं चल पाया।

इस दौरान परिजन भी मौके पर मौजूद रहे। परिजनों के अनुसार, नवनीत अपने बड़े भाई और चाचा के बेटे के साथ सेक्टर-31 गया था, जहां तीनों ने शराब पी। इसके बाद वे मोटरसाइकिल से एत्मादपुर पुल पहुंचे। रास्ते में नवनीत ने पहले पेशाब के बहाने गाड़ी रुकवाई और कुछ दूरी चलने के बाद दोबारा गाड़ी रुकवाकर अचानक पुल से नहर में छलांग लगा दी। नवनीत को बचाने के लिए उसका बड़ा भाई और चचेरा भाई भी नहर में कूद गए, लेकिन अंधेरा ज्यादा होने के कारण वे उसे नहीं बचा सके।

फर्नीचर गोदाम में लगी आग, सामान जलकर राख

फरीदाबाद,एजेंसी।

एक नंबर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर के सामने स्थित फर्नीचर बनाने के गोदाम में मंगलवार अचानक आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और गोदाम की पहली मंजिल से तेज धुआं व आग की लपटें बाहर निकलने लगीं। आग की सूचना मिलते ही एनआईटी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। घटना में गोदाम के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी भी प्रकार की जान का नुकसान नहीं हुआ।

एनआईटी फायर स्टेशन के अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि सुबह कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई कि एक नंबर माता वैष्णो देवी मंदिर के सामने एस. कुमार नामक की फर्नीचर गोदाम में आग लग गई। सूचना के बाद तुरंत टीम को अलर्ट किया गया और दो फायर गाडिय़ों के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर देखा गया कि गोदाम का शटर बंद था और पहली मंजिल से घना धुआं निकल रहा था, जिससे अंदर प्रवेश करना मुश्किल हो रहा था।

फायर कर्मियों ने पहले नीचे से ही पानी डालकर आग को काबू में करने का प्रयास किया। आग की लपटें बाहर तक तेजी से बाहर निकल रही थी, जिसकी वजह से पहली मंजिल की सभी शीशे की खिड़कियां टूट के सडक़ पर बिखर गई थी। इसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों को बुलाकर इलाके की बिजली सप्लाई बंद करवाई गई। शटर को काटकर गोदाम के अंदर प्रवेश किया गया, जहां आग पर काबू पाने का काम शुरू किया गया। गोदाम में लकड़ी, कपड़ा और फोम की अधिक मात्रा होने के कारण आग तेजी से फैल गई थी। बताया गया कि गोदाम में एक श्रमिक भी रहता था, लेकिन आग लगने के समय वह मंदिर गया हुआ था।

अपहरण और लूटपाट करने वाले दो बदमाश गिरफ्तार

गुरुग्राम,एजेंसी।

दिल्ली से सटे गुरुग्राम में राहगीरों को निशाना बनाकर अपहरण और लूटपाट करने वाले एक शातिर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए सेक्टर-65 थाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक मजदूर का अपहरण कर उसे जंगल में ले जाकर न केवल उसके साथ लूटपाट की, बल्कि उसके भाई को फोन कर उसे छोड़ने के बदले 25 हजार रुपये की मांग भी की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त ईको गाड़ी, पीड़ित का आधार कार्ड और लूटी गई नकदी बरामद कर ली है। मूल रूप से मध्य प्रदेश के सागर जिले का निवासी पीड़ित बहरामपुर इलाके में एक फार्म हाउस पर काम करता है।

13 दिसंबर की रात करीब साढ़े 12 बजे जब वह सेक्टर-17ए में अपने भाई से मिलने जा रहा था, तभी रास्ते में एक सफेद रंग की ईको गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में सवार दो युवकों ने उसे जबरन अंदर खींच लिया और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी पीड़ित को बहरामपुर के पास सुनसान जंगल में ले गए। वहां उन्होंने पीड़ित से पैसों की मांग की। जब पीड़ित ने खुद को गरीब बताते हुए पैसे न होने की बात कही, तो आरोपियों ने उसका मोबाइल और पर्स छीन लिया, जिसमें 1500 रुपये और आधार कार्ड था।

भाई को फोन कर मांगी फिरौती

लूटपाट के दौरान ही पीड़ित के मोबाइल पर उसके भाई का फोन आ गया। बदमाशों ने फोन उठाकर भाई को डराया कि पीड़ित उनके पास है और उसे सुरक्षित छोड़ने के बदले 25 हजार रुपये देने होंगे। घबराए भाई ने तुरंत 112 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना दी। इसी बीच, जब गाड़ी एक मोड़ पर धीमी हुई, तो पीड़ित साहस दिखाते हुए अपना मोबाइल छीनकर बदमाशों के चंगुल से कूदकर भाग निकला।

कुछ ही घंटों में पुलिस की बड़ी कार्रवाई

शिकायत मिलने के तुरंत बाद सेक्टर-65 थाना पुलिस ने तत्परता दिखाई। पुलिस टीम ने आरोपियों का पीछा करते हुए महज कुछ ही घंटों के भीतर गांव बालियावास से दोनों को काबू कर लिया। आरोपियों की पहचान 25 वर्षीय दीपक और 26 वर्षीय विकास निवासी गांव बंधवाड़ी, गुरुग्राम के रूप में हुई है। पुराना है आपराधिक रिकॉर्ड पुलिस पूछताछ में पता चला कि दोनों आरोपी पेशे से ईको गाड़ी चलाने का काम करते हैं और सुनसान रास्तों पर अकेले जा रहे लोगों को निशाना बनाते थे।

जांच में इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। आरोपी दीपक के खिलाफ पहले भी सेक्टर-56 थाने में अपहरण और लूट का मामला दर्ज है। आरोपी विकासभी एक आदतन अपराधी है, जिस पर फरीदाबाद और गुरुग्राम में लूट, अपहरण और मारपीट के कई संगीन मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों को दो दिन की रिमांड के बाद मंगलवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है।

विरोध के बाद अतिरिक्त चार्ज वापस

गुरुग्राम,एजेंसी।

जीएमडीए के इंफ्रा-एक के कार्यकारी अभियंता शेखर नांदल और उपमंडल अभियंता पवन कुमार से मोबिलिटी शाखा का अतिरिक्त चार्ज वापस ले लिया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा के निर्देश पर प्रशासनिक शाखा ने इस सिलसिले में आदेश जारी कर दिए हैं। गत 29 नवंबर को जीएमडीए के कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश बिदान ने इन दोनों अधिकारियों को मोबिलिटी शाखा का अतिरिक्त चार्ज सौंपा था, जिसके बाद मोबिलिटी शाखा में अंदरखाने विरोध शुरू हो गया था। यह मामला नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के समक्ष पहुंच गया था। मोबिलिटी शाखा में पहले से ही एक कार्यकारी अभियंता कार्यरत हैं। ऐसे में दोनों अधिकारियों का चार्ज वापस ले लिया गया।

बैंक्वेट हॉल में पेयजल की जांच होगी

गाजियाबाद,एजेंसी।

शादी समारोह से पहले स्वास्थ्य विभाग बैंक्वेट हॉल में इस्तेमाल होने वाले पेयजल की गुणवत्ता की जांच करेगा। इसके लिए जनवरी के अंतिम सप्ताह में स्वास्थ्य विभाग अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहा। मानक के अनुरूप पानी न मिलने पर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शुभ कार्य 14 दिसंबर से 45 दिन के लिए बंद हैं। 31 जनवरी से दोबारा शुरू होंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अभियान चलाकर पेयजल की जांच करने की योजना तैयार की है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. आरके गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रमों में दूषित या कम गुणवत्ता वाला पेयजल इस्तेमाल करने से बीमारियों का खतरा रहता है। इसको ध्यान में रखते हुए यह अभियान चलाया जाएगा। इसमें बैंक्वेट हॉल, सोसाइटी, आरओ प्लांट और घरों में भी पेयजल की जांच की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम पानी के सैंपल लेकर प्रयोगशाला भेजेगी।

गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता बहुत खराब, हाइब्रिड मोड में जारी रहेंगी प्राथमिक कक्षाएं

गुरुग्राम,एजेंसी।

गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता का स्तर बहुत खराब हो चुका है। एनसीआर क्षेत्र में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा लागू ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रेप) के प्रावधानों के मद्देनजर उपायुक्त अजय कुमार के 13 नवंबर को जारी किए गए आदेश अभी भी प्रभावी हैं। ऐसे में आगामी आदेशों तक यहां प्राथमिक स्तर तक की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में ही लगेंगी।

पिछले कई दिनों से गुरुग्राम जिले में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है, जिसके अंतर्गत कक्षा पांचवीं तक की पढ़ाई ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से की जा रही है। जहां ऑनलाइन शिक्षण की सुविधा उपलब्ध है, वहां अभिभावक एवं विद्यार्थी अपनी सहमति से ऑनलाइन विकल्प का चयन कर सकते हैं।

स्कूलों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो और शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। उपायुक्त अजय कुमार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि यह निर्णय सीएक्यूएम के 11 नवंबर 2025 के आदेश तथा राज्य सरकार द्वारा 12 नवंबर 2025 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है। इसके साथ ही जिले में ग्रेप-4 के तहत लागू सभी पाबंदियां भी प्रभावी रहेंगी। डीसी ने जिला शिक्षा अधिकारी, जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी सहित सभी सरकारी व निजी स्कूलों को इन आदेशों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

गायों को गौशाला तक लाने पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि: श्रवण कुमार

फरीदाबाद,एजेंसी।

हरियाणा गोसेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग ने मंगलवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बेसहारा गोवंश के पुनर्वास को ले समीक्षा बैठक की। बैठक में गोशालाओं की वर्तमान व्यवस्थाओं, क्षमता, सुविधाओं को लेकर चर्चा गई। बैठक में उप निदेशक पशुपालन, पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग के पशु डॉक्टरों, उपमंडल अधिकारियों, पुलिस विभाग के अधिकारियों, हरियाणा गो सेवा आयोग के पूर्व सदस्य तथा जिले की सभी गोशालाओं एवं नंदी शालाओं के प्रबंधकों ने भाग लिया।

अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग ने बताया कि सहारा पशुओं की देखभाल एवं संरक्षण को लेकर अभियान चलाया गया है। अभियान के अंतर्गत जो भी व्यक्ति बेसहारा पशुओं को पकडक़र नगर निगम फरीदाबाद या रजिस्टर गोशालाओं तक पहुंचाएगा, उसे प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि बेसहारा पशु के बच्चे (बछड़ा/बछिया) को लाने पर 300 रूपए, गाय को लाने पर 600 तथा बैल को लाने पर 800 रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ताकि अधिक से अधिक बेसहारा पशुओं को सडक़ों से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके।

उन्होंने बताया कि फरीदाबाद जिले में कुल 11 गोशालाएं कार्यरत हैं। इनमें से सात गोशालाएं हरियाणा गोसेवा आयोग द्वारा पंजीकृत हैं, तीन नगर निगम फरीदाबाद के अधीन संचालित हो रही हैं तथा एक गोशाला स्वतंत्र (इंडिपेंडेंट) रूप से कार्य कर रही है। इन सभी गोशालाओं को अभियान में सम्मिलित किया गया है, ताकि बेसहारा गोवंश के पुनर्वास की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित की जा सके। बैठक में गोशालाओं के निरीक्षण के दौरान गौशालाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन किया गया तथा जहां-जहां कमियां पाई गईं, वहां सुधार के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही गोशाला प्रबंधकों को अवगत कराया गया कि गोसेवा आयोग किस प्रकार से आर्थिक, प्रशासनिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है, ताकि बेसहारा पशुओं की देखभाल बेहतर ढंग से की जा सके।

पुलिस को चार नए पीआरवी वाहन मिले

गाजियाबाद,एजेंसी।

आपातकालीन पुलिस सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक लॉजिस्टिक की ओर से यूपी-112 परियोजना के द्वितीय चरण के तहत गाजियाबाद पुलिस को चार नए पीआरवी वाहन आवंटित किए गए हैं। इन नए वाहनों के शामिल होने से न केवल पुलिस का रिस्पांस टाइम बेहतर होगा, बल्कि संकट में फंसे पीड़ितों तक समय पर मदद पहुंचाना भी आसान हो सकेगा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इन चारों नए पीआरवी वाहनों को जिले के विभिन्न थानों में तैनात किया गया है। कविनगर और मोदीनगर थाना क्षेत्र को एक-एक पीआरवी वाहन दिया गया है, जबकि भोजपुर थानाक्षेत्र को दो नए वाहन आवंटित किए गए हैं।

इन क्षेत्रों में आबादी और घटनाओं की संवेदनशीलता को देखते हुए वाहनों का वितरण किया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच सके। सभी चारों नए पीआरवी वाहनों को मंगलवार को पुलिस लाइन से एसीपी यूपी-112 द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर यूपी-112 से जुड़ा समस्त पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। अधिकारियों ने बताया कि नए वाहन आधुनिक संचार उपकरणों और आवश्यक संसाधनों से लैस हैं, जिससे आपात कॉल मिलने पर पुलिस टीम तेजी से घटनास्थल तक पहुंचकर प्रभावी कार्रवाई कर सकेगी।

अधिकारियों का कहना है कि यूपी-112 के बेड़े में इन नए वाहनों के शामिल होने से कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने में मदद मिलेगी। साथ ही सड़क हादसों, अपराध, महिलाओं की सुरक्षा और अन्य आपात स्थितियों में पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान की जा सकेगी। पुलिस का दावा है कि आने वाले समय में यूपी-112 की सेवाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी, जिससे आम जनता का भरोसा पुलिस व्यवस्था पर और बढ़ेगा।

बदमाशों ने खड़ी थार को फूंका, पास खड़ी गाड़ी भी जली

गुरुग्राम,एजेंसी।

यहां एक घर के बाहर खड़ी थार गाड़ी में बदमाशों ने आग लगा दी। आग से थार गाड़ी तो जली ही, उसके साथ में खड़ी एक अन्य कार भी जल गई। आग की लपटें घर के अंदर तक गई तो घर में भी नुकसान हो गया। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने मंगलवार को बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार जिला के गांव सिधरावली में सोमवार की आधी रात को अज्ञात बदमाशों ने एक घर के बाहर खड़ी थार गाड़ी में आग लगा दी। कुछ ही देर में आग की लपटों से गाड़ी घिर गई।

थार के साथ में ही खड़ी एक मारुति वैगन आर कार में भी आग लग गई। देखते ही देखते आग दोनों गाडिय़ों में फैल गई और दोनों गाडिय़ां बुरी तरह से जल गई। साथ ही आग से घर में भी काफी नुकसान हो गया। आग की घटना को लेकर थार गाड़ी के मालिक रमन यादव का कहना है कि सोमवार की रात को पूरा परिवार घर में सो रहा था। आधी रात 12 बजे गली में शोर सुनाई दिया।

उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो उनकी थार गाड़ी में आग लगी थी। साथ ही पास में खड़ी वैगन आर गाड़ी भी उसकी चपेट में आ गई थी। पहले तो खुद ही बुझाने के प्रयास किए गए, लेकिन आग अधिक भडक़ती गई। फायर बिग्रेड को इस घटना की सूचना दी गई। मौके पर बिलासपुर पुलिस थाना से टीम व फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग बुझानी शुरू की। जब तक आग बुझायी जा सकी, तब तक गाडिय़ां पूरी तरह से जल चुकी थी। पीड़ित रमन यादव का कहना है कि उनकी गाड़ी के अक्टूबर माह में शीशे भी तोड़े गए थे।

तब भी पुलिस को शिकायत दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इस बार उनकी थार को आग ही लगा दी गई। पुलिस इस मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाली हैं। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि रात दो बजकर छह मिनट पर एक युवक कैन में पेट्रोल लेकर वहां पहुंचता है। वह सधे हुए कदमों से थार की तरफ बढ़ता है और उस पर पेट्रोल छिडक़ता है। इसके बाद आग लगाकर फरार हो जाता है।

गुर्जर क्रशर जोन में प्लास्टिक कबाड़ में लगी भीषण आग

गुरुग्राम,एजेंसी।

मंगलवार की सुबह बार गुर्जर क्रशर जोन प्लास्टिक कबाड़ में भीषण आग लग गई। आग की लपटें दूर तक ही दिखाई दी तो लोगों में हडक़ंप मच गया। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर बिग्रेड से गाडिय़ां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। दमकल विभाग के अधिकारी ललित ने मंगलवार को बताया कि प्राथमिक तौर पर आग लगने का कारण चिंगारी लग रहा है। जानकारी के अनुसार बार गुर्जर गांव के पास क्रशर जोन है। वहां पर प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग साइट है। सुबह करीब आठ बजे प्लास्टिक के सामान में आग लग गई गई। पहले तो धुआं उठा और काफी क्षेत्र में फैल गया।

देखते ही देखते आग की लपटें भी उठने लगीं। आग की सूचना पाकर लोगों में दहशत फैल गई। दूर तक आग की लपटें दिखीं तो लोगों में हडक़ंप मच गया। अधिक प्लास्टिक रखा होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना पाकर विभाग की टीमें गाडिय़ों के साथ मौके पर पहुंची। तुरंत ही आग बुझानी शुरू कर दी। दमकल विभाग के अधिकार ललित के अनुसार दो गाडिय़ों आग बुझाने के लिए मौके पर भेजी गई। प्लास्टिक के सामान में लगी आग काफी भडक़ चुकी थी।

जहरीला धुओं भी उत्पन्न हो रहा था। ऐसे में आग बुझाने में कर्मचारियों को काफी परेशानी हो रही थी। दमकल विभाग की ओर से आसपास के लोगों को घटनास्थल से दूर भेज दिया गया, ताकि किसी को धुएं से कोई दिक्कत ना हो। दमकल विभाग की टीमों ने आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की। तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। माना जा रहा है कि किसी चिंगारी के कारण यह आग लगी है। हालांकि आग के कारणों की जांच भी की जा रही है।

RNI.No DLHIN/25/A2841 स्वामी, प्रकाशक, संपादक देवेंद्र सिंह तोमर एवं मुद्रक रवि भारद्वाज मे. मारुती नंदन प्रिंटर्स एवं पब्लिशर, शक्ति कॉम्प्लेक्स 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली 110042 से मुद्रित एवं हॉउस नंबर 16/ 9980, गली नंबर-5, सराय रोहिल्ला न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005 से प्रकाशित।

संपादकीय कार्यालय - B4/265B केशव पुरम नई दिल्ली -110005। फोन-011-40106508 मोबाइल-9911466900/ 8076353913। Email.saahassamachardainik@gmail.com

संपादक देवेंद्र सिंह तोमर

इस अंक में प्रकाशित खबरों एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। किसी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा नई दिल्ली के न्यायालय में होगा।

सरकार पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के बच्चों को लाभार्थी नहीं, परिवार का सदस्य मानती है: रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, पीएम सरकार का उद्देश्य केवल तात्कालिक सहायता देना नहीं, बल्कि इन बच्चों को सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त जीवन की ओर अग्रसर करना है।

नई दिल्ली,साहस समाचार।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम के दौरान पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत पंजीकृत बच्चों से आत्मीय बातचीत की। यह कार्यक्रम उन बच्चों के सहयोग, संरक्षण और संवेदनशील देखभाल को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता, कानूनी अभिभावक अथवा दत्तक माता-पिता को खो दिया है। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और भावनात्मक आवश्यकताओं के बारे में जानकारी ली और उन्हें हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इन बच्चों को केवल किसी योजना के लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि अपने परिवार के सदस्य के रूप में देखती है और उनके सुरक्षित व सम्मानजनक भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने बच्चों को चॉकलेट भेंट कर स्नेह प्रकट किया तथा प्रत्येक बच्चे का उसके संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से परिचय कराया, ताकि बच्चों को यह भरोसा मिल सके कि प्रशासन हर स्तर पर उनके साथ खड़ा है। इस अवसर पर संबंधित जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के सभी प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य केवल तात्कालिक सहायता देना नहीं, बल्कि इन बच्चों को सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त जीवन की ओर अग्रसर करना है। उन्होंने जानकारी दी कि दिल्ली में इस योजना का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो बच्चों के संरक्षक के रूप में उनकी निरंतर निगरानी और देखभाल सुनिश्चित कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 मई 2021 को प्रारंभ की गई पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना उन बच्चों के लिए है, जिन्होंने वर्ष 2020 से शुरू हुई कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता, कानूनी अभिभावक अथवा दत्तक माता-पिता को खो दिया। इस योजना का उद्देश्य बच्चों की समग्र देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना, शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से उनके सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना तथा 23 वर्ष की आयु तक उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और आवास से संबंधित विभिन्न लाभ प्रदान किए जाते हैं, जिससे बच्चों के सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखी जा सके।

एयरपोर्ट पर 48 करोड़ का गांजा पकड़ा, 6 यात्री गिरफ्तार

नई दिल्ली,साहस समाचार।

नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई) पर कस्टम विभाग के अधिकारियों ने नशीले पदार्थों की तस्करी का खुलासा किया है। यह कार्रवाई बैंकॉक से आने वाली फ्लाइट नंबर टीजी-323 से 11 दिसंबर 2025 को टर्मिनल-3 पर पहुंचे छह भारतीय यात्रियों के खिलाफ की गई। कस्टम अधिकारियों को इन यात्रियों की गतिविधियों पर शक हुआ, जिसके बाद उन्हें ग्रीन चैनल पर रोका गया। शक के आधार पर यात्रियों के सामान को एक्स-रे मशीन से स्कैन किया गया और उनकी व्यक्तिगत तलाशी भी ली गई।

जब उनके ट्रॉली बैग्स की गहन जांच की गई तो दो ग्रे रंग, एक हरे रंग और एक टील रंग के ट्रॉली बैग से कुल 24 पॉलिथीन पाउच बरामद हुए। इन पाउचों के अंदर हरे रंग का नशीला पदार्थ पाया गया, जिसे प्राथमिक जांच में गांजा/मारिजुआना बताया गया है। जब इस पदार्थ को तौला गया तो इसका कुल वजन 48.016 किलोग्राम (नेट वजन) निकला। मौके पर की गई प्रारंभिक जांच से यह पुष्टि हुई कि बरामद किया गया पदार्थ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित गांजा/मारिजुआना है। अधिकारियों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 48.01 करोड़ रुपये आंकी गई है।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि सभी छह यात्रियों ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8 का उल्लंघन किया है। उन पर धारा 20, 23 और 29 के तहत अपराध करने का मामला बनता है, जो मादक पदार्थों के अवैध कब्जे, तस्करी और आपराधिक साजिश से संबंधित हैं।

इसके बाद कस्टम अधिकारियों ने सभी छह यात्रियों को 12 दिसंबर 2025 को दोपहर 1:05 बजे से 1:30 बजे के बीच एनडीपीएस एक्ट की धारा 43(बी) के तहत गिरफ्तार कर लिया।

द्वारका में स्कूटी हटाने को लेकर खूनी संघर्ष

नई दिल्ली,साहस समाचार।

पश्चिमी दिल्ली में द्वारका के बाबा हरिदास नगर इलाके में घर के बाहर सड़क पर खड़ी एक स्कूटी हटाने को लेकर शुरू हुए मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दो पड़ोसी पक्षों के बीच हुए इस झगड़े में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित पक्ष ने गंभीर आरोप लगाया है कि आरोपियों ने पुलिस के मौके पर मौजूद होने के बावजूद उन्हें बुरी तरह घायल किया और फिर फरार हो गए।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि नजफगढ़ स्थित जनता कॉलोनी निवासी पीड़ित दलबीर सिंह ने अपने बयान में बताया कि 10 दिसंबर को उनके घर पशुओं के लिए रिक्शा से चारा आया था। रिक्शा को अंदर लाने के लिए दलबीर ने अपने पड़ोसी संजय से सड़क पर खड़ी स्कूटी हटाने के लिए कहा। स्कूटी हटाने की बात सुनते ही संजय और उसके परिवार वाले भड़क गए और झगड़ा शुरू कर दिया।

दलबीर सिंह का आरोप है कि संजय, उसके बेटे फौजी, संजय की पत्नी, फौजी की पत्नी और अन्य लोगों ने मिलकर पहले दलबीर और उसके पोतों की जमकर पिटाई की। पीड़ित का आरोप है कि इसी दौरान उनकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन संजय के घर बाहर से आए लोगों ने पुलिसकर्मियों के सामने ही उन पर तेज धार हथियारों से हमला कर दिया। पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन हमलावरों की संख्या अधिक होने के कारण पुलिस उन्हें तुरंत काबू नहीं कर सकी।

इसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया, जिसे देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए। जांच के दौरान पुलिस ने संजय की छत पर छिपे हुए तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया। हमले में घायल हुए दलबीर सिंह, दक्ष और निशांत को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। बाबा हरिदास नगर थाना पुलिस ने पीड़ित पक्ष के बयान के आधार पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है।

अंतरराष्ट्रीय 'डिजिटल अरेस्ट' ठगी गिरोह का पर्दाफाश, 10 गिरफ्तार

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दक्षिण-पूर्व जिला पुलिस की शाहीन बाग थाना टीम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय एक बड़े डिजिटल ठगी व उगाही गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपितों के खिलाफ राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर 66 शिकायतें दर्ज हैं और करीब 50 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी का लेन-देन इनसे जुड़ा हुआ है। गिरोह के दो अन्य सदस्य अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है।

पुलिस ने इस कार्रवाई के तहत दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र (मुंबई), ओडिशा, पंजाब, उप्र और हरियाणा सहित सात राज्यों में एक साथ छापेमारी की। इस दौरान एक आरोपी को मुंबई एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया गया, जब वह दुबई भागने की फिराक में था। दक्षिण पश्चिम जिले के पुलिस उपायुक्त डॉ. हेमंत तिवारी ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि सात दिसंबर को शाहीन बाग निवासी तनबीर अहमद ने शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि उसे व्हाट्सऐप वीडियो कॉल के जरिए धमकाया गया।

कॉल करने वालों ने खुद को कर्नाटक पुलिस अधिकारी बताया और कहा कि उसका आधार नंबर व मोबाइल नंबर गंभीर अपराधों में इस्तेमाल हुआ है। गिरफ्तारी के डर से पीड़ित ने 99,888 रुपये ठगों के बताए खाते में ट्रांसफर कर दिए। इस शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना शाहीन बाग में विशेष टीम गठित की गई।

टीम ने वित्तीय लेन-देन, तकनीकी सुराग और डिजिटल ट्रेल का गहन विश्लेषण किया। लगातार तकनीकी निगरानी और फील्ड इनपुट के आधार पर आरोपितों की लोकेशन ट्रैक की गई। दिल्ली, उप्र, केरल, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और ओडिशा में फैले नेटवर्क को खंगालते हुए पुलिस ने रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जैसे अहम स्थानों पर दबिश देकर आरोपितों को दबोच लिया। पुलिस अधिकारी के अनुसार अब तक गिरोह के 10 मुख्य सदस्यों को पकड़ा गया है। इनमें म्यूल अकाउंट होल्डर, फसिलिटेटर, सिम एक्टिवेशन और फंड हैंडलर शामिल हैं।

पकड़ा गया धर्मेंद्र चौहान म्यूल अकाउंट जुटाने और ठगी की रकम निकालने में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। वहीं सोमवीर सैनी गिरोह को वाहन और म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराने का काम करता था। जबकि मो. एहतेशामुल हक मुख्य समन्वयक, म्यूल अकाउंट के जरिए रकम घुमाने और कैश हैंडओवर में शामिल था। इसी क्रम में संतोष कुमार खंडाई अवैध सिम एक्टिवेशन और व्हाट्सऐप अकाउंट की मदद करता था। इसके अलावा मुहम्मद बुगारी ठगी की रकम हैंडल करने वाला अहम सदस्य था। इसके खातों पर एनसीआरपी में कई शिकायतें दर्ज। वहीं मुहम्मद शाहिद डेबिट कार्ड और संचार व्यवस्था का संचालन करता था।

वायु प्रदूषण हार्ट के लिए घातक: डॉ. कालरा

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली-एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ऐसी स्थिति में थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। यह बात कालरा अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. आर.एन. कालरा ने एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम के साथ बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन गया है, जो खासतौर पर हार्ट और मधुमेह रोगियों के लिए अधिक जोखिमपूर्ण है।

डॉ. कालरा ने सलाह दी कि ऐसे मरीज घर से बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल करें और अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच कराते रहें। उन्होंने बताया कि भले ही सर्दियों को आमतौर पर स्वास्थ्य के लिए बेहतर मौसम माना जाता है, लेकिन इस दौरान उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों को अपने खान-पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि चलने-फिरने या सांस लेने में दिक्कत, घबराहट या बेचैनी जैसे लक्षण महसूस हों तो तुरंत चिकित्सकीय जांच करानी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में उच्च रक्तचाप से ग्रसित लोगों में हृदय रोग के लक्षण अधिक देखने को मिलते हैं।

पांच साल से फरार रोहित बलारा गिरफ्तार

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पैरोल पर 5 साल से फरार रोहित बलारा को द्वारका से गिरफ्तार किया है। आरोपी को नेब सराय थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय नाबालिग लड़के के साथ यौन शोषण के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है और वह 2021 से फरार था। पुलिस के अनुसार, रोहित बलारा को कोविड-19 महामारी के दौरान वर्ष 2021 में 90 दिनों की इमरजेंसी पैरोल दी गई थी, लेकिन पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और फरार हो गया। जेल प्रशासन की तरफ से बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और लगातार फरार चल रहा था।

मुखर्जी नगर में युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला

नई दिल्ली,साहस समाचार।

राजधानी के मुखर्जी नगर इलाके में युवती से कहासुनी के बाद हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि युवती के जानकारों ने एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जख्मी युवक को तत्काल एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने इस मामले में हत्या के प्रयास की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने एक महिला समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है।

पकड़े गए आरोपियों की पहचान मुखर्जी नगर निवासी रमेश, गौतम, सत्यम और एक महिला के रूप में हुई है। सोमवार को पुलिस को चाकूबाजी की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि घायल को पहले ही अस्पताल ले जाया जा चुका है। इसके बाद पुलिस टीम एलएनजेपी अस्पताल पहुंची और पीड़ित का बयान दर्ज किया। पीड़ित ने बताया कि वह अपने भाई के साथ गुरुद्वारे के पास स्थित एक रेस्तरां में खाना खाने गया था।

वहां एक युवती नशे की हालत में चार-पांच युवकों के साथ मौजूद थी और इसी दौरान किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। दोनों भाई किसी तरह वहां से निकल गए, लेकिन कुछ देर बाद रेस्तरां के पास ही आरोपियों ने उनमें से एक भाई को पकड़ लिया। आरोप है कि एक युवक ने चाकू से हमला कर उसके पेट और हाथ पर वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित का यह भी कहना है कि घटना के दौरान साथ मौजूद युवती हमलावरों को उकसा रही थी।

घटना के बाद दोनों भाई किसी तरह अपने पीजी आवास पहुंचे और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

दिल्ली पुलिस ने शातिर बदमाश को दबोचा

नई दिल्ली,साहस समाचार।

पश्चिमी दिल्ली में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 40 से अधिक आपराधिक मामलों में वांछित शातिर बदमाश ऋषभ को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई में कीर्ति नगर थाने के एक बहादुर कॉन्स्टेबल ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए हाई-स्पीड पीछा कर आरोपी को दबोचा। आरोपी ऋषभ चोरी की हाई-स्पीड केटीएम बाइक पर खुलेआम घूम रहा था और हैरानी की बात यह रही कि बाइक पर असली नंबर प्लेट लगी हुई थी। पुलिस के अनुसार, इसी नंबर प्लेट के कारण वह विभिन्न स्थानों पर लगे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरों में कैद हो गया।

पश्चिमी जिले के डीसीपी डी. शरद भास्कर ने बताया कि ऋषभ की तलाश शालीमार बाग, मोती नगर और मायापुरी थानों की पुलिस को भी थी। एएनपीआर कैमरों से मिले इनपुट के आधार पर जानकारी कीर्ति नगर थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई शुरू की गई। एसीपी पंजाबी बाग शिवम और एसएचओ संजीव डोढी के निर्देशन में जांच के दौरान, कीर्ति नगर थाने के कॉन्स्टेबल नवीन ने पेट्रोलिंग के समय संदिग्ध केटीएम बाइक को पहचान लिया। बिना किसी देरी के उन्होंने अकेले ही बाइक का पीछा शुरू किया।

पुलिस के मुताबिक, बदमाशों ने जिग-जैग तरीके से भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रैफिक जाम का फायदा उठाकर कॉन्स्टेबल नवीन ने साहस दिखाते हुए बाइक पर झपट्टा मारा। बाइक फिसल गई और दोनों आरोपी गिर पड़े। मौके पर ही ऋषभ को पकड़ लिया गया, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। जांच में सामने आया कि ऋषभ अगस्त में एक पुराने मामले में जमानत पर जेल से बाहर आया था और इसके बाद फिर से चोरी व छीना-झपटी की घटनाओं को अंजाम देने लगा। उसकी निशानदेही पर एक और स्कूटी भी बरामद की गई है, जिसका इस्तेमाल वह वारदातों में करता था। पुलिस का दावा है कि ऋषभ की गिरफ्तारी से मायापुरी, मोती नगर और शालीमार बाग थानों में दर्ज कम से कम आधा दर्जन मामलों का खुलासा हो गया है। फरार साथी की तलाश जारी है।

चिड़ियाघर में दो चौसिंगा हिरण की मौत

नई दिल्ली,साहस समाचार।

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (चिड़ियाघर) में पिछले सप्ताह दो चौसिंगा हिरणों की मौत हो गई। इस प्रजाति के बचे हुए अन्य दो हिरणों को एहतियात के तौर पर क्वारंटाइन में रखकर निगरानी में रखा गया है। चिड़ियाघर के एक अधिकारी ने बताया कि दोनों मौतें अचानक हुई। एक हिरण की मौत बाड़े में हुई, जबकि दूसरे की उपचार के लिए ले जाने के बाद मौत हो गई। अधिकारी के अनुसार, मुंह से झाग निकलने के लक्षण पाए गए हैं, जिससे रेबीज की आशंका जताई जा रही है।

हालांकि, वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2016 में भी चिड़ियाघर में चीतल हिरणों में रेबीज फैला था, जिसमें कुछ ही समय में 30 से अधिक वन्यजीवों की मौत हो गई थी। उस समय नेवले के काटने को इसका कारण माना गया था। अब भी इसी तरह की संभावना की जांच की जा रही है।

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि रेबीज फैलने की आशंका चूहों के जरिए भी जताई जा रही है। चिड़ियाघर परिसर में चूहों की संख्या कम करने के लिए जहर का इस्तेमाल किया जा रहा है और यह भी देखा जा रहा है कि कहीं इसका कोई असर तो नहीं पड़ा।

पहले कॉल कर परिवार को धमकी दी, फिर दो भाइयों को भून डाला

नई दिल्ली,साहस समाचार।

जाफराबाद के चौहान बांगर इलाके में सोमवार देर रात अंधाधुंध फायरिंग कर दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान 33 वर्षीय नदीम और 31 वर्षीय फैजल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने करीब 40 राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही जाफराबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों भाइयों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हत्या में शामिल आरोपी मृतकों की बुआ का बेटा और उसके सहयोगी हैं। पुलिस को वारदात से पहले पीड़ित परिवार को धमकी भरा फोन भी मिला था।

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि दोनों भाई गली नंबर 30/8 में अपने परिवार के साथ रहते थे और उनका निजी व्यवसाय था। सोमवार रात करीब 1:40 बजे फायरिंग की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। फैजल को घटनास्थल पर मृत पाया गया, जबकि नदीम को उसका भाई वसीम स्कूटी से अस्पताल ले गया। अस्पताल पहुंचने पर नदीम को भी मृत घोषित कर दिया गया। मौके से चार तरह के कारतूस मिले पुलिस ने घटनास्थल से 40 से अधिक कारतूस बरामद किए।

सूत्रों के अनुसार, नदीम को लगभग 15 और फैजल को 20 गोलियां लगीं। गोली चलाने वाले चार आरोपी थे और हर एक के पास अलग हथियार थे। पुलिस को चार अलग-अलग प्रकार के खाली कारतूस मिले, जिससे पता चलता है कि वारदात में चार तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इस घटना ने स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। समझौते के बाद वारदात वसीम ने बताया कि उनकी बुआ का बेटा असद दोनों भाइयों से पहले से रंजिश रखता था। सोमवार को परिवारों के बीच करीब ढाई घंटे चली बैठक में समझौता हुआ, लेकिन असद ने रंजिश रखते हुए देर रात दोनों भाइयों को घेरकर गोली मार दी।

नदीम 85 फीसदी दिव्यांग थे। बदमाशों ने दोनों पर नजदीकी से गोली चलाई और फिर फरार हो गए। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया जाफराबाद थाना ने हत्या और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और पुलिस उसकी पूछताछ कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही हैं और मृतकों के परिवार के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं।

डीयू के नए नियम से विवाद, शिक्षकों और शोधकर्ताओं में नाराजगी

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए लागू किए गए एक नए नियम को लेकर व्यापक नाराजगी देखने को मिल रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्देश जारी किया है कि अब किसी भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने या शोध पत्र प्रस्तुत करने से पहले शिक्षकों को एक विशेष समिति से पूर्व अनुमति लेनी होगी। इस फैसले को शिक्षकों ने अकादमिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने वाला बताया है।

नए नियम के अनुसार, किसी भी सम्मेलन में शोध पत्र प्रस्तुत करने के इच्छुक शिक्षक को कम से कम दो महीने पहले अपने शोध पत्र का पूरा मसौदा और सम्मेलन से जुड़ी सभी जानकारियां विश्वविद्यालय को सौंपनी होंगी। इसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति न केवल शोध पत्र की विषयवस्तु का मूल्यांकन करेगी, बल्कि सम्मेलन आयोजित करने वाली संस्था की विश्वसनीयता की भी जांच करेगी। समिति की स्वीकृति के बाद ही शिक्षक को सम्मेलन में शामिल होने की अनुमति मिलेगी।

शिक्षकों और शिक्षाविदों का कहना है कि इस तरह की व्यवस्था से अकादमिक गतिविधियों पर अनावश्यक निगरानी बढ़ेगी और स्वतंत्र विचार एवं शोध प्रभावित होंगे। उनका मानना है कि इसका सबसे ज्यादा असर सामाजिक विज्ञान और मानविकी विषयों पर पड़ेगा, जहां शोध और अध्ययन का सीधा संबंध समाज, राजनीति और समसामयिक मुद्दों से होता है। विभिन्न शिक्षक संगठनों ने इस नियम का विरोध करते हुए कहा है कि विश्वविद्यालयों का उद्देश्य विचारों पर नियंत्रण नहीं, बल्कि खुली बहस और स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देना होना चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से इस नियम को तुरंत वापस लेने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि इसका विरोध नहीं किया गया।

संपादकीय

प्रदेश अध्यक्ष और योगी आदित्यनाथ: कमजोरी का संकेत या रणनीतिक संतुलन?

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष को लेकर उठी राजनीतिक चर्चाएँ इस समय राज्य की राजनीति का केंद्र बन गई हैं। उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का "विरोधी" बताए जाने से यह धारणा तेजी से फैल रही है कि शायद योगी की पकड़ अब पहले जैसी मज़बूत नहीं रही। लेकिन राजनीति में प्रतीक, पद और संदेश अक्सर सतही नहीं होते। इस नियुक्ति को सीधे-सीधे योगी की कमजोरी से जोड़कर देखना न केवल जल्दबाज़ी है, बल्कि भाजपा की कार्यशैली और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक प्रकृति को न समझ पाने का संकेत भी है।

भाजपा की राजनीति व्यक्तियों से अधिक संगठन पर आधारित रही है। प्रदेश अध्यक्ष का पद संगठन को चलाने, चुनावी मशीनरी को सक्रिय रखने और सामाजिक संतुलन साधने का माध्यम होता है, जबकि मुख्यमंत्री सरकार का चेहरा, निर्णयकर्ता और जनता के सामने उत्तरदायी नेतृत्व होता है। योगी आदित्यनाथ आज भी उत्तर प्रदेश में शासन, प्रशासन और राजनीतिक नैरेटिव के केंद्र में हैं। कानून-व्यवस्था, माफिया विरोधी अभियान और हिंदुत्व की स्पष्ट राजनीति ने उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया है, जिसकी पहचान केवल पार्टी तक सीमित नहीं रही। ऐसे में यह सवाल उठता है कि यदि योगी की पकड़ कमजोर होती, तो क्या पार्टी केवल संगठनात्मक स्तर पर बदलाव तक सीमित रहती? राजनीतिक इतिहास बताता है कि जब किसी मुख्यमंत्री की स्थिति वास्तव में कमजोर होती है, तो उसके संकेत मंत्रिमंडल, प्रशासनिक नियंत्रण और नेतृत्व के विकल्पों में दिखाई देने लगते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई संकेत फिलहाल नहीं दिखता। सत्ता का वास्तविक नियंत्रण अब भी योगी आदित्यनाथ के पास है और निर्णयों की दिशा वही तय करते हैं।

नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष को योगी विरोधी कहे जाने की धारणा दरअसल भाजपा की उस रणनीति को दर्शाती है, जिसमें सत्ता और संगठन के बीच संतुलन बनाए रखा जाता है। योगी आदित्यनाथ भाजपा के पारंपरिक संगठनात्मक ढांचे से नहीं, बल्कि जनसमर्थन और प्रशासनिक सख़्ती से उभरे नेता हैं। ऐसे नेताओं के साथ पार्टी अक्सर संगठन में एक अलग धुरी खड़ी करती है, ताकि शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण न हो। इसे टकराव नहीं, बल्कि संतुलन की राजनीति कहा जाना चाहिए।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और विविध राज्य में 2027 का चुनाव केवल एक चेहरे के भरोसे नहीं लड़ा जा सकता। भाजपा यह अच्छी तरह समझती है कि सत्ता बनाए रखने के लिए संगठन को मज़बूत, सक्रिय और सामाजिक रूप से प्रतिनिधि बनाना ज़रूरी है। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति इसी तैयारी का हिस्सा है, जिससे नाराज़ वर्गों, क्षेत्रीय असंतोष और जातीय समीकरणों को साधा जा सके। यह योगी की कमजोरी नहीं, बल्कि उनके नेतृत्व को चुनावी स्तर पर और प्रभावी बनाने की कोशिश भी हो सकती है। हालांकि यह भी सच है कि योगी सरकार के सामने चुनौतियाँ कम नहीं हैं। बेरोज़गारी, महंगाई, ग्रामीण असंतोष और युवाओं की आकांक्षाएँ ऐसे मुद्दे हैं, जो यदि समय रहते संबोधित नहीं किए गए तो 2027 में राजनीतिक नुकसान का कारण बन सकते हैं। इन सवालों से आँख मूँदना किसी भी मजबूत नेता के लिए जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन इन चुनौतियों का अस्तित्व होना और नेतृत्व का कमजोर होना—दो अलग-अलग बातें हैं। प्रदेश अध्यक्ष की नई भूमिका दरअसल योगी सरकार के लिए एक राजनीतिक कुशन की तरह है। संगठन सरकार से जुड़े असंतोष को संभालेगा, टिकट वितरण और सामाजिक संतुलन साधेगा, जबकि योगी अपने प्रशासनिक और वैचारिक एजेंडे पर केंद्रित रहेंगे। भाजपा का यह मॉडल पहले भी कई राज्यों में देखा गया है, जहाँ मजबूत मुख्यमंत्री के साथ संगठनात्मक संतुलन बनाया गया। निष्कर्षतः, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष को योगी आदित्यनाथ का विरोधी मानकर यह कहना कि उत्तर प्रदेश में योगी की पकड़ कमजोर हो रही है, एक सरलीकृत और अधूरा विश्लेषण है। वास्तविकता यह है कि भाजपा 2027 को केवल व्यक्तित्व के भरोसे नहीं, बल्कि संगठन और सरकार की संयुक्त शक्ति के साथ लड़ने की तैयारी कर रही है। योगी आदित्यनाथ आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे प्रभावशाली चेहरा हैं, और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति उनके विरुद्ध नहीं, बल्कि उसी राजनीतिक लड़ाई को और व्यवस्थित करने का संकेत है।

मानसिकता और कार्यक्षमता को प्रभावित करती वर्चुअल मीटिंग्स

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

डिजिटल क्रांति ने कार्य दिवस के परंपरागत समय सीमा को बदल कर रख दिया है। कहने को तो छह या सात घंटे का कार्य दिवस होता है पर वर्चुअल युग में कर्मचारी 24 गुणा 7 के दौर में आ गया है। इससे कार्मिकों की मानसिकता और सामाजिक-इकोनॉमिक ताने-बाने को भी प्रभावित किया है।

डिजिटल क्रांति ने कार्य दिवस के परंपरागत समय सीमा को बदल कर रख दिया है। कहने को तो छह या सात घंटे का कार्य दिवस होता है पर वर्चुअल युग में कर्मचारी 24 गुणा 7 के दौर में आ गया है। इससे कार्मिकों की मानसिकता और सामाजिक-इकोनॉमिक ताने-बाने को भी प्रभावित किया है। एक समय था जब शीर्ष या पहली दूसरी कतार के अधिकारियों की जिम्मेदारी अधिक होती थी और उनके लिए समय सीमा नहीं होती थी पर अब तो वर्चुअल सुविधाओं के चलते दिन हो या रात, रविवार हो या शनिवार कभी भी कहीं भी एक मैसेज मात्र से आपको एक्टिव होकर कैमरे के सामने आना पड़ता है।

दरअसल, कोरोना काल ने यह परिवर्तन दिया है। भारत सहित दुनिया के देशों में अभी भी कार्मिकों के लिए कार्य दिवस पांच या छह दिवस के हैं तो कार्यसमय भी मानने को तो सुबह 9.30 से सायं बजे 6 या दूसरे शब्दों में औसतन लगभग सात घंटे का है पर डिजिटल क्रान्ति ने सबकुछ बदल कर रख दिया है। देखा जाए तो अब असीमित कार्य दिवस का दौर आ गया है। वास्तविकता तो यह है कि डिजिटल डिवाइसों के उपयोग के बाद से कमोबेश कार्यदिवस 24 गुणा 7 हो गये हैं तो कार्य समय भी तय समय सीमा के बंधन से मुक्त हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कराये गये वर्क ट्रेंड इंडेक्स स्पेशल रिपोर्ट 2025 में यह खुलासा हो गया है कि अब कार्मिक चाहे वह किसी भी स्तर का हो, उसके लिए चाहे निजी क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में तय समय सीमा बीते जमाने की बात हो गई है। ई-मेल, चैट, वर्चुअल या हाईब्रिड मीटिंग्स, सोशल मीडिया संदेश आदि को समग्र रुप से देखने से अब कार्मिक 24 घंटे का कार्मिक हो गया है।

वर्क ट्रेंड इंडेक्स स्पेशल रिपोर्ट के अनुसार सुबह छह बजे से ही व्यक्ति अपनी ई-मेल टटोलने लगता है तो सर्वाधिक प्रोडक्टिविटि का समय 11 बजे के लगभग में काम के स्थान पर ई-मेल का प्रेशर 54 प्रतिशत तक बढ़ जाता है सायं तीन बजे बाद ई-मेल, चैट या अन्य संदेशों की आवक कम होने लगती है। वैश्विक औसत की बात की जाये तो 100 से अधिक ई-मेल से दो-चार होना पड़ता है कार्मिक को। हर दो मिनट में मेल, चैट या अन्य संदेश कार्मिक के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। इसका कारण यह होता है कि उसे कॉल, ई-मेल या संदेश चेक करने या उससे दो-चार होना ही पड़ता है।

हालात यह है कि रात को भी ई-मेल या संदेश का सिलसिला जारी रहने से अब कार्यालयीय वातावरण से दूर परिवार के व्यैयक्तिक क्षण तो कल्पना की बात होती जा रही है।

डिजिटल क्रांति के चलते मीटिंग्स खासतौर से वर्चुअल या हाईब्रिड मीटिंग्स सुविधाजनक होने के साथ ही

कार्मिकों के तनाव का कारण भी बनती जा रही है। हालांकि वैश्विक ट्रेंड के अनुसार मंगलवार को सर्वाधिक मीटिंग्स होती है इनमें

माइक्रोसॉफ्ट की हालिया रिपोर्ट से यह साफ हो गया है कि डिजिटल युग को देखते हुए अब कार्मिकों के कार्यदिवस को नए सिरे से री-डिजाइन करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। इसका प्रमुख कारण कार्मिकों शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ना और सामाजिकता और वैयक्तितता पर विपरीत प्रभाव पड़ना प्रमुख हो जाता है। समय-बेसमय मोबाइल या इसी तरह की डिवाइस पर अंगुलियां चलाने से प्रभावित हो रहे हैं। काम का दबाव, सूचनाओं के संग्रहण में ही समय जाया होने, वर्चुअल मीटिंग्स में सार्वजनिक रुप से जलालत की संभावना, आंखों में सूखापन और सामाजिक व व्यक्तिगत संबंध बाधित होना आम होता जा रहा है। इसका साइड इफेक्ट संत्रास, कुंठा, तनाव, डिप्रेशन आदि के रुप में सामने आने लगा है। इसके समाधान के लिए हालांकि विशेषज्ञों ने फ्रंटियर फर्म की आवश्यकता प्रतिपादित की है। इसमें आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस के माध्यम से विश्लेषण की बात की जाने लगी है। पर समय की मांग और आवश्यकता यह महसूस की जाने लगी है कि वर्क कल्चर को रिडिजाइन किया जाएं। अन्यथा देर-सबेर इसके नकारात्मक प्रभावों से बचना मुश्किल हो जाएगा।

खासतौर से एडहॉक मीटिंग्स अधिक होती है तो शुक्रवार को अपेक्षाकृत मीटिंग्स का दबाव कम होता है। सबसे खास बात यह कि औसतन 10 में से एक मिटिंग तो बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक तय होती है। एक और खास यह कि वर्चुअल मीटिंग्स सुविधाजनक होने और अपना संदेश संबंधित सभी तक पहुंचाने का बेहतरीन माध्यम होने के बावजूद यह तनाव का कारण तो बनता ही है इसके साथ ही गुणवत्ता पर भी प्रश्न लगाये जाने लगे हैं। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि दस में से एक मीटिंग लास्ट टाइम बुक की जाती है तो मीटिंग्स में प्रस्तुत होने वाले पॉवर प्वाइंट प्रजेंटेशन में मीटिंग के दस मिनट पहले तक आंशिक बदलाव या अपडेशन होता है। यह कोई किसी एक पक्ष यानी सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठान की बात या किसी देश विशेष की बात ना होकर वैश्विक वास्तविकता है।

विशेषज्ञों की मानें तो अंतिम समय तक प्रजेंटेशन में बदलाव का मतलब ही यह है कि गुणवत्ता कहीं ना कही प्रभावित हो रही है। वैश्विक आंकड़े तो यही कहते हैं कि अंतिम समय में पीपीटी में अपडेशन या संशोधन में 122 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। वर्चुअल मीटिंग का सिलसिला दरअसल कोरोना महामारी के दौर से अधिक सामने आया है और इसे समय और धन बचाने में सहायक माना जाता है पर मीटिंग्स के दौर जिस तरह से बढ़ने लगे हैं उससे कार्मिक सूचनाएं संग्रहित करने और उसमें अपने बचाव के उपाय खोजने में ही अपनी अधिकांश कार्यक्षमता व्यय कर देता है और परिणाम स्वरुप कार्य में गुणवत्ता और उत्पादकता में कमी आना स्वाभाविक माना जाने लगा है।

माइक्रोसॉफ्ट की हालिया रिपोर्ट से यह साफ हो गया है कि डिजिटल युग को देखते हुए अब कार्मिकों के कार्यदिवस को नए सिरे से री-डिजाइन करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। इसका प्रमुख कारण कार्मिकों शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ना और सामाजिकता और वैयक्तितता पर विपरीत प्रभाव पड़ना प्रमुख हो जाता है। समय-बेसमय मोबाइल या इसी तरह की डिवाइस पर अंगुलियां चलाने से प्रभावित हो रहे हैं। काम का दबाव, सूचनाओं के संग्रहण में ही समय जाया होने, वर्चुअल मीटिंग्स में सार्वजनिक रुप से जलालत की संभावना, आंखों में सूखापन और सामाजिक व व्यक्तिगत संबंध बाधित होना आम होता जा रहा है। इसका साइड इफेक्ट संत्रास, कुंठा, तनाव, डिप्रेशन आदि के रुप में सामने आने लगा है। इसके समाधान के लिए हालांकि विशेषज्ञों ने फ्रंटियर फर्म की आवश्यकता प्रतिपादित की है। इसमें आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस के माध्यम से विश्लेषण की बात की जाने लगी है। पर समय की मांग और आवश्यकता यह महसूस की जाने लगी है कि वर्क कल्चर को रिडिजाइन किया जाएं। अन्यथा देर-सबेर इसके नकारात्मक प्रभावों से बचना मुश्किल हो जाएगा।

दरअसल, यह अपने आपमें गंभीर समस्या हो गई है। इसका समाधान हर स्तर पर खोजना होगा। यह कोई कार्यालयीय समस्या, सामाजिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या या शारीरिक मानसिक समस्या ना होकर पूरे ताने-बाने को ही प्रभावित करने वाली समस्या है। ऐसे में विशेषज्ञों, गैर-सरकारी संगठनों, मनोविज्ञानियों के साथ ही मानव संसाधन विशेषज्ञों और नियोक्ताओं को भी इस समस्या का समाधान खोजना होगा।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

न्यायपालिका के खिलाफ विपक्षी राजनीति का महाभियोग!

मनोज कुमार अग्रवाल

क्या न्यायपालिका को अपनी निष्पक्षता साबित करने के लिए सनातन धर्म और बहुसंख्यक हिन्दू समाज के खिलाफ फैसला देना जरूरी है? क्या इस देश में बहुसंख्यक आस्था के पक्ष में मेरिट के आधार पर भी कोई न्यायिक निर्णय देना तथाकथित सेकुलर सियासतदानों की नजर में अपराध है? इन दिनों मद्रास हाइकोर्ट के न्यायाधीश के एक फैसले को लेकर देश की कथित सेकुलरिज्म की झंडाबरदार राजनीति में हलचल मची हुई है। ये वही सियासतदान हैं जो आजादी के बाद पिछले सात दशक तक अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की सियासती आंच पर अपनी रोटी सकते रहे उन्हें एक नयायाधीश का एक दीप जलाने की इजाजत देने वाला फैसला जहर लग रहा है। अब विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के 107 सांसदों ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन को पद से हटाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक महाभियोग प्रस्ताव सौंपा है । इस प्रस्ताव में कांग्रेस, डीएमके आप , सपा, सीपीआई, सीपीएम, और शिवसेना (उद्धव ठाकरे) सहित कई प्रमुख दलों के सांसदों के हस्ताक्षर हैं। नियम के अनुसार, किसी जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है,इंडिया ब्लॉक के 107 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पर दस्तखत किए हैं।

आपको बता दें कि इस पूरे राजनीतिक विवाद की पृष्ठभूमि में न्यायमूर्ति स्वामीनाथन का एक फैसला है। पिछले हफ्ते, उन्होंने तमिलनाडु के तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित 6वीं शताब्दी के सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के प्रशासन को एक निर्देश दिया। यह निर्देश था कि 13वीं शताब्दी की सिकंदर बादुशाह दरगाह के पास एक स्तंभ पर दीपक जलाने की परंपरा को फिर से शुरू किया जाए। जब राज्य सरकार ने विरोध किया और मंदिर प्रबंधन ने पालन नहीं किया, तो जज ने अवमानना का आदेश भी जारी किया।न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने अपने आदेशों का पालन न करने पर तमिलनाडु के मुख्य सचिव और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) को 17 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने के लिए भी तलब किया है। उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, मैं यहां हाथ उठाकर असहाय होकर यह कहने के लिए नहीं हूं कि, हे पिता, उन्हें माफ कर दो, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। यह जानबूझकर उल्लंघन है। उन्होंने केओसुबल की रिपोर्ट का संज्ञान लिया, जिसमें बताया गया था कि मदुरै पुलिस आयुक्त ने 200 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ अदालत के आदेश का पालन करने से केओसुबल टुकड़ी को रोका था। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्टों के 56 पूर्व न्यायाधीशों ने विपक्षी सांसदों द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग की पहल को लेकर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पूर्व न्यायाधीशों ने कहा कि यह कदम उन न्यायाधीशों को दबाव में लाने का प्रयास है जो राजनीतिक या वैचारिक उम्मीदों के अनुरूप फैसले नहीं देते। 12 दिसंबर को जारी संयुक्त बयान में उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बुनियाद को कमजोर करते हैं। उन्होंने कहा कि महाभियोग का इस्तेमाल न्यायिक आचरण की रक्षा के लिए होता है, न कि राजनीतिक हथियार की तरह।

मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन को हटाने की मांग करते हुए 100 से अधिक सांसदों की ओर से लाए गए महाभियोग प्रस्ताव के खिलाफ बड़ा विरोध सामने आया। 50 से अधिक पूर्व न्यायाधीशों, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और कई हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं, ने एक कड़े शब्दों वाला पत्र जारी कर इस कदम की कड़ी निंदा की। उन्होंने इस कदम को जजों को डराने-धमकाने की खुली कोशिश बताया। पूर्व जजों ने कहा कि कार्तिगई दीपम दीप-प्रज्वलन मामले में दिए गए निर्णय के आधार पर जस्टिस स्वामीनाथन को हटाने की कोशिश लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जड़ें हिला देने वाली है। उन्होंने लिखा कि सांसदों द्वारा बताए गए कारण सतही और इतने गंभीर संवैधानिक कदम के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं हैं।

पत्र में पूर्व जजों ने इस कोशिश को न्यायपालिका को कमजोर करने वाली लंबी और चिंताजनक राजनीतिक परंपरा का हिस्सा बताया। उन्होंने आपातकाल के बाद तीन वरिष्ठ जजों की सुपरसिडिंग, जस्टिस एचआर खन्ना की उपेक्षा और पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़ और अब सीजेआई सूर्यकांत के खिलाफ चलाए गए राजनीतिक अभियान का उल्लेख किया। पूर्व न्यायाधीशों ने चेतावनी दी कि महाभियोग जैसे संवैधानिक प्रावधान का इस्तेमाल आर्म-ट्विस्टिंग और बदले की राजनीति के हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, "आज निशाना एक जज है, कल पूरा संस्थान निशाने पर होगा।"

पूर्व जजों ने सांसदों, बार काउंसिल, सिविल सोसाइटी और नागरिकों से अपील की कि इस कदम को शुरुआत में ही रोक दिया जाए, क्योंकि जज संविधान के प्रति जवाबदेह होते हैं, न कि राजनीतिक समूहों की पसंद-नापसंद के प्रति कोई जबाबदेही

बता दें कि यह पूरा विवाद तमिलनाडु में तब उठा, जब जस्टिस स्वामीनाथन ने तिरुप्परंकुंद्रम हिल पर दीपथून स्तंभ पर कार्तिगई दीपम का दीप जलाने का आदेश दिया। यह स्थान सिकंदर बादूशा दरगाह के पास है और लंबे समय से संवेदनशील माना जाता रहा है। याचिकाकर्ताओं की मांग पर जज ने 4 दिसंबर शाम 6 बजे तक दीप जलाने का निर्देश दिया। उन्होंने दलील दी कि यह कदम मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता, लेकिन दीप न जलाने से पहाड़ी पर मंदिर के अधिकार कमजोर हो सकते हैं, क्योंकि वहां कथित अतिक्रमण की शिकायतें उठती रही हैं।

हालांकि तमिलनाडु सरकार ने यह कहते हुए कि इससे कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है, आदेश लागू करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस और हिंदू संगठनों के बीच झड़पें भी हुईं। डीएमके ने आरोप लगाया कि जज ने 2017 की डिवीजन बेंच के आदेश को उलट दिया है और उनका निर्देश चुनाव से ठीक पहले सांप्रदायिक तनाव भड़का सकता है। पार्टी नेता टीआर बालू ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि बीजेपी राज्य में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। वहीं तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष नैनार नागेन्द्रन ने महाभियोग प्रस्ताव को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि डीएमके न्यायिक फैसले तभी स्वीकार करती है जब वे उसके हित में हों। भाजपा नेता ने कहा कि जस्टिस स्वामीनाथन ने कोई अपराध नहीं किया और मंदिर व पुलिस प्रशासन की विफलता के कारण ही उन्हें आदेश देना पड़ा। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के महाभियोग प्रयास गलत परंपरा कायम करेंगे और संस्थानों के बीच टकराव को जन्म दे सकते हैं। आपको पता रहे यह मुद्दा सिर्फ अदालत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पिछले हफ्ते लोकसभा में भी बवाल मच गया था। डीएमके सदस्यों ने सदन में विरोध प्रदर्शन करते हुए बीजेपी पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया। वहीं, केंद्रीय उपमंत्री एल. मुरुगन ने डीएमके पर एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने का पलटवार किया।

सनातन का विरोध ही सेक्युलर राजनीति है ?

भारत विभाजन के साथ मिली स्वाधीनता से कोई सबक न लेते हुए भारत की राजनीति आज तक तुष्टिकरण के आधार पर चलती रही है। मुस्लिम वोटबैंक को प्रसन्न करने के लिए बिहार का मुख्यमंत्री रहते तथाकथित समाजवादी लालू प्रसाद यादव ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को जेल में डाल दिया, उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए मुलायम सिंह ने निहत्थे रामभक्तों को गोलियों से भुनवा दिया, कांग्रेस साम्प्रदायिक हिंसा बिल ले आई। वो तो भला हो उस समय विपक्ष में होने के बाद भी भाजपा ने इसे पारित होने से बचा लिया। मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण ही पाकिस्तान को सटीक उत्तर देने की जगह अमन का तमाशा किया जाता रहा।

मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए भारत की सनातन संस्कृति को अनेकानेक प्रकार से चोट पहुंचाई जाती रही। वर्ष 2014 में केन्द्रीय नेतृत्व प्रदान करते हुए नरेन्द्र मोदी ने तुष्टिकरण के कारण सनातन संस्कृति को हुई क्षति की भरपाई के प्रयास शुरू किए।

ताजा बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद एक बार फिर मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले दल अधिक कटु होकर सनातन हिंदू धर्म पर प्रहार कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनकी दो दिवसीय भारत यात्रा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्रीमद्भगवद्गीता का रूसी अनुवाद भेंट किया। इसको देखकर कांग्रेस और वामपंथी दलों ने न केवल प्रधानमंत्री वरन श्रीमद्भगवद्गीता के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करते हुए इसका विरोध किया। कांग्रेसियों ने गीता के लिए मूल शब्द का प्रयोग किया जो एक अक्षम्य अपराध है।

वर्ष 2026 में पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हैं, अतः इन दो प्रान्तों में सनातन प्रतीकों तथा हिन्दू समाज को अपमानित करने का कार्य भी सबसे अधिक और सबसे तेजी से हो रहा है। पश्चिम बंगाल में वहां के तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर ने बाबर के नाम की मस्जिद की आधारशिला रखी और प्रशासन चुपचाप खड़ा रहा क्योंकि इस हरकत को मुख्यमंत्री का मौन समर्थन था। उसकी देखा-देखी बिहार और तेलंगाना में भी कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं ने बाबरी नाम की मस्जिद व स्मारक बनाने का ऐलान करके साप्रंदायिक तनाव बढ़ाने का काम आरम्भ कर दिया है। इस बाबरी भूत को वह सभी दल प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से समर्थन दे रहे हैं जिनकी राजनीति मुस्लिम तुष्टिकरण से चलती है और जो संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमते हैं।

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया सपरिवार शौर्य दिवस को सलीम चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ा कर हिन्दुओं को चिढ़ाते दिखे। सपा मुखिया का तुष्टिकरण में संलिप्त यह कृत्य जनता समझ रही है। सपा मुखिया समय-समय पर ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे सनातन हिन्दू समाज आहत हो। महाकुंभ से लेकर लेकर अयोध्या के दीपोत्सव तक उन्होंने हिन्दू परम्पराओं का उपहास करते हुए उन्हें ढोंग बताया।

वहीं, कांग्रेस ने तो हिंदू सनातन आस्था के सभी केन्द्रों का अपमान करने की सुपारी ही ले रखी है। कर्नाटक में तो मुस्लिम तुष्टिकरण का खुला खेल चल ही रहा है। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह "सुक्खू" की कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार को हिंदू बच्चों के राधे-राधे बोलने पर आपत्ति है। तेलंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी लगातार सनातन और हिंदुओं के विरुद्ध आग उगल रहे हैं।

रेवंत रेड्डी ने हिंदुओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि हर व्यक्ति और हर काम के लिए एक अलग भगवान होता है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा हिंदू कितने भगवानों को मानते हैं? तीन करोड़ हैं, इतने सारे क्यों हैं? जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए एक भगवान है -हनुमान, जो लोग दो शादी करते हैं उनके लिए अलग भगवान हैं और जो लोग शराब पीते हैं- मुर्गा खाते हैं, उनके लिए अलग भगवान हैं। हर ग्रुप का अलग भगवान है।

रेड्डी के बयान से हिंदुओं की भावनाओं का आहत होना स्वाभाविक था । हिंदू संगठनों ने मुख्यमंत्री से माफी मांगने को कहा किंतु मुस्लिम परस्त रेवंत रेड्डी अपने बयान पर कायम हैं। उधर, तमिलनाडु में भगवान मुरुगन के मंदिर में दीप जलाने को लेकर द्रमुक सरकार मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए न्यायालय की भी अवहेलना कर रही है। तमिलनाडु से ही हिन्दू और सनातन समाज को डेंगू-मलेरिया जैसे रोगों की संज्ञा दी जाती रही है।

कांग्रेस जीत जाये तो सिकंदर और हार जाये तो अंपायर खराब- ये तरीका ठीक नहीं: नड्डा

नई दिल्ली, एजेंसी।

राज्य सभा में चुनाव सुधारों पर जवाब देते हुए सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि 'कांग्रेस जब जीत जाये तो सिकंदर और हार जाये तो अंपायर खराब-ये तरीका ठीक नहीं है। कांग्रेस सरकार के जमाने में बैलेट बॉक्स खुलेआम लूटे जाते और गायब हो जाते थे। चुनाव आयोग की रिपोर्ट है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा उन्हें सीधे तौर पर किसी भी तरह के चुनाव सुधार का सुझाव नहीं दिया गया।' उन्होंने पूछा कि कांग्रेस फिर से पुराने लालटेन युग में क्यों जाना चाहती है?

चुनाव सुधारों पर चर्चा का समापन करते हुए मंगलवार को जेपी नड्डा ने कहा कि 'दशकों तक चुनाव आयोग के काम को देखने की जिम्मेदारी एक पार्टी की थी और वो पार्टी एक परिवार की पार्टी है।

उस दौर में किसी ने इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े नहीं किये। जब हम सुधार की बात करते हैं तो एसआईआर को लेकर देशभर में ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास हुआ कि जैसे कोई धांधली हो रही है। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर रैली कर रही है। लोकतांत्रिक प्रणाली की सशक्ति पर कांग्रेस के पुराने नेताओं और आज के नेताओं की बात करें तो स्पष्ट होता है कि गंगा-जमुना में कितना ज्यादा पानी बह चुका है।' उन्होंने कहा कि 'देश में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) कोई नया नहीं है। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते वर्ष-1952, 1957, 1961 में देश में एसआईआर हुआ।

अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़कर सारे एसआईआर कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार में हुए हैं। बिहार चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए तकलीफ दायक है, लेकिन वे जनता और अपने ही कार्यकर्ताओं को एसआईआर पर दोष मढ़कर गलत अफवाह फैला रहे हैं।' उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि

'कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग जितने भी आरोप लगाये उसके जवाब में आयोग ने तर्कपूर्ण जवाब दिये।

कांग्रेस द्वारा देश को गुमराह करना देशहित में नहीं है। चुनाव आयोग के साथ कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल खड़े किये हैं। उन्हें ये समझना होगा कि राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते देश में ईवीएम आया, जिसमें कई वैधानिक प्रावधान हुए थे।' जेपी नड्डा ने कहा कि 'कांग्रेस पार्टी 58 साल से तमिलनाडु में चुनाव नहीं जीत पा रही, दिल्ली में 12 साल से सरकार में नहीं है। पश्चिम बंगाल में 48 साल से सरकार में नहीं है। बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश में 35 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है। झारखंड में कांग्रेस की सरकार कभी नहीं रही। उड़ीसा में 25 साल से सरकार में नहीं है और केरल में 11 साल से सरकार में नहीं है।

कांग्रेस नेताओं को समझना होगा कि चुनाव आयोग पर नहीं, बल्कि अपनी कार्यशैली पर मंथन करने की जरूरत है।

कांग्रेस ने इस साल फरवरी में चुनाव में धांधली को लेकर बार-बार आरोप लगाए और हर बार अलग आँकड़ा प्रस्तुत किया। इससे समझ आता है कि वे चुनाव प्रक्रिया को लेकर कितने गंभीर हैं।'

उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को समझना होगा कि एसआईआर केवल चुनाव जीतने-हारने का नहीं बल्कि देश का विषय है। हमारे लिए देश पहले होना चाहिए इसके बाद बाकी विषय होना चाहिए। हम सभी बातों पर पूरी तरह से चर्चा के लिए तैयार हैं। हमारे लिए दल बाद में है और देश पहले है।

मप्र सरकार ने उज्जैन का लैंड पूलिंग एक्ट लिया वापस, आदेश जारी

भोपाल, एजेंसी। मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र में जमीनों के स्थाई अधिग्रहण को लेकर लाया गया लैंड पूलिंग एक्ट वापस ले लिया है। विधायकों और भारतीय किसान संघ के लगातार विरोध के बाद सरकार ने यह फैसला किया है। मंगलवार देर शाम नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल, लैंड पूलिंग एक्ट के तहत सरकार विकास परियोजनाओं के लिए किसानों से जमीन लेती है, फिर उसी क्षेत्र को विकसित कर उसका एक हिस्सा वापस मालिकों को प्लॉट या विकसित भूमि के रूप में देती है। सरकार का दावा रहा कि इससे किसानों को जमीन का बेहतर मूल्य और शहर को सुनियोजित विकास मिलता है, लेकिन उज्जैन में इस एक्ट को लेकर किसानों की आपत्ति यह रही कि जमीन देने की प्रक्रिया स्वैच्छिक नहीं लगी, विकसित जमीन कब और कितनी मिलेगी, इस पर स्पष्टता नहीं दिखी ।

उल्लेखनीय है कि सिंहस्थ और महाकाल लोक से जुड़े क्षेत्रों में जमीनों की कीमत बहुत अधिक है, ऐसे में किसान नुकसान की आशंका जता रहे थे। कुछ गांवों में बिना पर्याप्त सहमति के सर्वे और नोटिस की बात सामने आई। इन्हीं कारणों से उज्जैन में लैंड पूलिंग एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ा। उज्जैन उत्तर से भाजपा विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर इस विवाद की ओर ध्यान दिलाया था।

इतिहास भूलने वाला देश अपना अस्तित्व खो देता है : राज्यपाल

कोलकाता, एजेंसी।

1971 के भारत–पाकिस्तान युद्ध में ऐतिहासिक विजय की स्मृति में कोलकाता स्थित पूर्वी कमान मुख्यालय विजय दुर्ग में विजय दिवस का भव्य आयोजन किया गया,जिसमें मिजोरम के राज्यपाल जनरल वी.के. सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे।

विजय दिवस के अवसर पर मीडिया से बातचीत में जनरल वी.के. सिंह ने भारत–बांग्लादेश संबंधों और साझा इतिहास पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जो देश अपना इतिहास भूल जाता है, उसका अस्तित्व लंबे समय तक नहीं टिक पाता।

1971 के युद्ध को साहस, बलिदान और निर्णायक नेतृत्व का प्रतीक बताते हुए उन्होंने कहा कि यह दिन सम्मान और गर्व के साथ याद किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की इच्छा है कि बांग्लादेश में सुख-शांति बनी रहे और उसका आर्थिक विकास और अधिक सशक्त हो। भारत–बांग्लादेश संबंधों पर जनरल सिंह ने कहा कि दोनों देश हमेशा से एक-दूसरे के सहयोगी रहे हैं और यह मित्रता भविष्य में भी बनी रहेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि विजय दिवस दोनों देशों के वीर सपूतों के सम्मान का दिन है, न कि किसी राजनीतिक विवाद का मंच। पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रयासों की सराहना की।

केरल स्थानीय चुनावों में एसडीपीआई ने जीतीं 102 सीटें

कोच्चि,एजेंसी। प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से कथित संबंधों को लेकर जांच के दायरे में रही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) ने केरल के हालिया स्थानीय निकाय चुनावों में पूरे राज्य में 102 सीटें जीती हैं।

एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष सी पी ए लतीफ के अनुसार पार्टी ने दो नगर निगमों, एक ब्लॉक पंचायत, आठ नगर पालिकाओं और 91 ग्राम पंचायतों में सीटें हासिल कीं हैं। उन्होंने इस प्रदर्शन को 'मजबूत' बताते हुए कहा कि यह सफलता निरंतर प्रशासनिक दबाव और राजनीतिक निशाना बनाए जाने के बावजूद हासिल की गयी है।

भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए तैयार: अनुराग

नई दिल्ली, एजेंसी।

पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए पूरी तैयार है।

संसद भवन में मंगलवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राजग की सरकार बनी तो पहले ही दिन से खेल के प्रति सरकार का रुख स्पष्ट था।

खिलाड़ी देश के लिए खेलते हैं इसलिए उनकी ट्रेनिंग और जरूरतों को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। सरकार का स्पष्ट मानना है कि खेलेगा भारत और बढ़ेगा भारत। खेल के क्षेत्र में हम पहले पांच स्थान में गिने जाने की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं और साल 2030 तक भारत की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री 120 बिलियन डॉलर हो जाएगी। आज भारत अपने सामर्थ्य के दम पर 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए तैयार है।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एक युवा एवं खेल मंत्रालय को 800 करोड़ रुपये के आसपास का बजट देकर निपटा दिया जाता था, आज युवा एवं खेल मंत्रालय का कुल बजट 3,794.30 करोड़ रुपये है। देशभर में महिला खेलों को बढ़ावा देने के लिए अस्मिता योजना के अंतर्गत देशभर में 20 खेलों का आयोजन किया गया। इसमें कुल 766 प्रतियोगिताओं में 83,763 महिला खिलाड़ियों की भागीदारी

कबड्डी खिलाड़ी की सरेआम हत्या ने खोली मान सरकार की कानून व्यवस्था की पोल : चुग

नई दिल्ली, एजेंसी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी की सरेआम हत्या को पंजाब में फैली अराजकता और कानून व्यवस्था के पूर्ण पतन का प्रतीक बताया। मंगलवार को मीडिया से बातचीत में तरुण चुग ने कहा कि सरेआम एक खिलाड़ी की हत्या हो जाती है और पूरी मान सरकार मौन साधे बैठी है, जो बेहद शर्मनाक और चिंताजनक है।

चुग ने कहा कि पंजाब में भगवंत मान सरकार के संरक्षण में गैंगस्टर, अपराधी और हथियारबंद गिरोह बेखौफ घूम रहे हैं। जिस पंजाब ने देश को असंख्य खेल प्रतिभाएं दीं, वहीं आज खिलाड़ी सुरक्षित नहीं हैं। यह घटना केवल एक खिलाड़ी की हत्या नहीं, बल्कि पंजाब की खेल प्रतिभा और उसकी पहचान की हत्या है। तरुण चुग ने कहा कि जिस पंजाब की धरती ने भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए, उसी धरती पर इस तरह की घटनाएं यह स्पष्ट करती हैं कि आम आदमी पार्टी के शासन में पंजाब में कानून का राज समाप्त हो चुका है और जंगलराज हावी हो गया है। अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ चुका है कि वे भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक मंचों पर भी गोलियां चलाने से नहीं डर रहे। तरुण चुग ने इस जघन्य अपराध की तुरंत, निष्पक्ष और प्रभावी जांच की मांग करते हुए कहा कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए।

नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत का संज्ञान नहीं लेना क्लीन चिट नहीं: गौरव

नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्यवाही को लेकर आ रही प्रतिक्रियाओं के बीच तीखा हमला बोलते हुए स्पष्ट किया कि 'अदालत का संज्ञान नहीं लेना क्लीन चिट नहीं होता और कानून हैशटैग (प्रतीकात्मक चिह्न) से नहीं चलता। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने एक पोस्ट कहा जिस आदेश को कांग्रेस जीत के रूप में पेश कर रही है, वह तकनीकी और प्रक्रियात्मक आधार पर है, न कि मामले के गुण-दोष पर।

अदालत ने न तो आरोपियों की बेगुनाही पर कोई टिप्पणी की है और न ही लेन-देन की वैधता या धनशोधन के आरोपों को खारिज किया है।

उच्च शिक्षा के नियमन में एकरूपता लाने के लिए नया शिक्षा विधेयक जरूरी : धर्मेन्द्र प्रधान

नई दिल्ली, एजेंसी।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक को समय की मांग बताते हुए मंगलवार को कहा कि उच्च शिक्षा के नियमन, मानक निर्धारण और विश्वविद्यालयों के प्रत्यायन में एक समान व्यवस्था लाने की आवश्यकता है, ताकि इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के अनुरूप बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि यह विधेयक सोमवार को संसद में पेश किया गया, जिसे विपक्ष के विरोध के बीच संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है।

प्रधान ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रस्तावित विधेयक के तहत नियमन, मानक निर्धारण और प्रत्यायन के लिए तीन अलग-अलग परिषदों का गठन किया जाएगा, जो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान के साथ समन्वय में कार्य करेंगी।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि वर्तमान में उच्च शिक्षा क्षेत्र में कई नियामक, मानक निर्धारण और प्रत्यायन निकाय कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) एक साथ नियामक, मानक निर्धारण और प्रत्यायन की भूमिका निभाता रहा है, जिससे हितों के टकराव और वस्तुनिष्ठता की कमी जैसी समस्याएं सामने आईं। समय के साथ एआईसीटीई, एनसीटीई और संसद के अधिनियमों के तहत बने राष्ट्रीय महत्व के संस्थान अस्तित्व में आए, वहीं वास्तुकला परिषद जैसे निकाय भी कार्यरत हैं। ऐसे में सभी को एक समान ढांचे के अंतर्गत लाने की जरूरत महसूस की गई।

प्रधान ने बताया कि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान के अंतर्गत तीन स्वायत्त परिषदें होंगी— विकसित भारत शिक्षा विनियमन परिषद (नियामक), विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद (प्रत्यायन) और विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद (मानक निर्धारण)। ये तीनों परिषदें स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगी, जबकि शिक्षा अधिष्ठान समन्वय की भूमिका निभाएगा।

राज्य विश्वविद्यालयों से जुड़ी आशंकाओं पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यूजीसी में राज्यों की भूमिका सीमित रही है, लेकिन नई व्यवस्था मौजूदा ढांचे के भीतर ही समन्वय सुनिश्चित करेगी।

इस बीच, प्रस्तावित विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों के वित्तपोषण की व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला गया। वर्तमान प्रणाली के अनुसार केन्द्र सरकार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को यूजीसी के माध्यम से और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को सीधे अनुदान देती है।

सार समाचार

अरुणाचल प्रदेश में शांति की रीढ़ है असम राइफल्स: राज्यपाल

ईटानगर,एजेंसी। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) के.टी. परनाइक ने मंगलवार को कहा कि निरंतर सतर्कता और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के माध्यम से असम राइफल्स ने अपने कार्यक्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की है। लोक भवन के एक अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल ने मंगलवार को ईटानगर में असम राइफल्स की 11वीं बटालियन को राज्यपाल प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। यह प्रशस्ति पत्र बटालियन के कमांडेंट कर्नल विवेक त्रिपाठी ने सूबेदार मेजर लेख राज और राइफलमैन (जीडी) नीलेश कुमार के साथ, बटालियन के सभी रैंकों की ओर से प्राप्त किया।

चरित्र निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण संभव: होसबले

संतकबीर नगर, एजेंसी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि चरित्र निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण संभव है। भारत की सांस्कृतिक जड़ें एक हैं, उपासना पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हमारे पूर्वज और मूल एक ही हैं। उन्होंने सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्य को जीवन में उतारने का आह्वान किया।

संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले आज संतकबीर नगर के बड़गो, खलीलाबाद में आयोजित हिंदू सम्मेलन को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित कर रहे थे। हिंदू समाज की एकता, सामाजिक समरसता एवं सांस्कृतिक चेतना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता महंत कबीर मठ मगहर के महंत विचार दास ने की। कार्यक्रम स्थल भगवा ध्वज व तोरणद्वारों से सजाया गया था।

सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने सामाजिक चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि अब समाज के सभी लोगों को सामाजिक समरसता को बढाना होगा और पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्य को जीवन में उतारते हुए राष्ट्र के लिए जियें। उन्होंने कहा कि चरित्र निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण संभव है और संगठित समाज ही राष्ट्र को परम वैभव पर ले जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक जड़ें एक हैं। उपासना पद्धतियां अलग हो सकती है, लेकिन हमारे पूर्वज और मूल एक ही है। यहां राष्ट्र की रक्षा ही धर्म की रक्षा है, क्योंकि धर्म केवल पूजा-पाठ नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति है।

सरकार्यवाह दत्तात्रेय ने आगे कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस प्राचीन राष्ट्र को आधुनिक काल में परम वैभव पर ले जाने के लिए प्रयत्नशील है। उन्होंने संघ संस्थापक डा. केशव बलिराम हेडगेवार के विचारों को रेखांकित करते हुए स्पष्ट किया कि केवल व्यक्ति का अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसमें राष्ट्रबोध और समाज बोध होना भी आवश्यक है। व्यक्तिगत चरित्र से राष्ट्रीय चरित्र को लक्ष्य बनाकर ही संघ और शाखा की संकल्पना की गई है। हिंदू संगठनों में इस सम्मेलन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। सम्मेलन में साधु-संत, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी समेत आम जन की व्यापक सहभागिता रही।

पतंजलि के सहयोग से त्रिपुरा बनेगा आर्गेनिक स्टेट

हरिद्वार,एजेंसी। त्रिपुरा के सतत और स्थायी विकास हेतु आज मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा की गरिमामयी उपस्थिति में प्रदेश सरकार और पतंजलि योगपीठ के मध्य एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

इसके तहत अब पतंजलि त्रिपुरा में एग्रोफ़ॉरेस्ट्री, जैविक कृषि, परंपरागत बीज संरक्षण, सप्लाई चेन, मार्केटिंग, वेलनेस टूरिज्म, मूल्य आधारित शिक्षा, योग, आयुर्वेद, कौशल विकास, नवाचार और अनुसंधान, आई टी टेक्नोलॉजी और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में संयुक्त रूप से कार्य करेगा।

त्रिपुरा को आर्गेनिक स्टेट बनाने हेतु पतंजलि ट्रेनिंग, तकनीकी और प्रामाणिकीकरण हेतु कार्य करेगा।

देशभर में 2,626 रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा से संचालित

नई दिल्ली, एजेंसी।

भारतीय रेल ने स्वच्छ और सतत ऊर्जा के उपयोग की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। देशभर में अब 2,626 रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, जिससे न केवल ऊर्जा लागत में कमी आई है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल रेलवे संचालन को भी बढ़ावा मिला है।

रेल मंत्रालय के अनुसार चालू वित्त वर्ष में इस पहल को और गति मिली है। नवंबर 2025 तक 318 नए स्टेशनों को सोलर नेटवर्क से जोड़ा गया, जिसके बाद सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशनों की कुल संख्या 2,626 हो गई है।

भारतीय रेल ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम हासिल करते हुए नवंबर 2025 तक 898 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता कमीशन की है। यह वर्ष 2014 में मात्र 3.68 मेगावाट से लगभग 244 गुना वृद्धि को दर्शाता है। कुल स्थापित सौर क्षमता में से 629 मेगावाट का उपयोग ट्रैक्शन प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है, जिससे विद्युत ट्रेनों के संचालन को सीधा समर्थन मिल रहा है। शेष 269 मेगावाट का उपयोग नॉन-ट्रैक्शन जरूरतों जैसे स्टेशन प्रकाश व्यवस्था, कार्यशालाओं, सेवा भवनों और रेलवे आवासों के लिए किया जा रहा है।

प्रवती परिदा का नवीन पटनायक पर जुबानी हमला

भुवनेश्वर,एजेंसी। ओडिशा की उप मुख्यमंत्री प्रवती परिदा ने पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक पर भुवनेश्वर में हुई नाबालिग लड़की से जुड़ी दुखद घटना पर राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया है। यह घटना हाल ही में सामने आई थी, जिस पर नवीन पटनायक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सरकार की आलोचना की थी। उप मुख्यमंत्री ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी कड़ी निंदा की और कहा कि राज्य के लोग ऐसे बड़े नेता से इस तरह की संवेदनशील और दर्दनाक घटना को राजनीतिक रंग देने की उम्मीद नहीं करते। उन्होंने पोस्ट में तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लिखा कि नवीन पटनायक कब सच बोलना शुरू करेंगे।

आधुनिक पढ़ाई को नैतिकता के साथ जोड़ना ज़रूरी : राष्ट्रपति मुर्मु

नई दिल्ली, एजेंसी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार को कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए आधुनिक पढ़ाई को नैतिकता के साथ जोड़ना ज़रूरी है। उन्होंने यह बातें कर्नाटक के मांड्या जिले के मालवल्ली में आदि जगद्गुरु श्री शिवरात्रीश्वर शिवयोगी महास्वामीजी के 1066वें जयंती समारोह का उद्घाटन के अवसर पर कही।

उन्होंने कहा, विकसित भारत के लिए शिक्षा, नैतिकता, नवाचार, जिम्मेदारी, विकास, समावेश और करुणा का एकीकृत मार्ग अपनाना होगा। राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि 'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई क्षेत्रों में समाकलन आवश्यक है। उन्होंने ज़ोर दिया कि देश की प्रगति के लिए आधुनिक शिक्षा को नैतिक ज्ञान के साथ जोड़ना जरूरी है।

राष्ट्रपति ने सुत्तूर मठ जैसे संस्थानों की सराहना करते हुए कहा कि वे इस राष्ट्रीय प्रयास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे मठ और संस्थाएं आध्यात्मिक मार्गदर्शन के साथ-साथ शिक्षा तथा सामाजिक सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकते हैं।

यह गीत आज भी प्रासंगिक है और हमें आगे बढ़ने और राष्ट्र हित में लगातार प्रयत्न करने की प्रेरणा देता है

विश्व को एक सूत्र में पिरोने वाला गीत है वंदे मातरम : तोमर

भोपाल, एजेंसी।

मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारा गौरव, हमारा अभिमान राष्ट्र गीत वंदे मातरम् न सिर्फ भारत को वरन पूरी दुनिया को एक सूत्र में और सही दिशा में ले जाने की भावना से लिखा गया गीत है। इसे सिर्फ गीत कहना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत का भी पर्याय है जो हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हमें किस पथ पर क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि यह गीत आज भी प्रासंगिक है और हमें आगे बढ़ने और राष्ट्र हित में लगातार प्रयत्न करने की प्रेरणा देता है। विधानसभा अध्यक्ष तोमर मंगलवार शाम को श्री अरविंद सोसायटी, शाखा भोपाल के दिव्यांश रजत जयंती समारोह में ₹श्री अरविंद का भारत और वंदे मातरमश्र विषय पर आयोजित विमर्श को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अरविंद की व्याख्या करते हुए कहा कि वे आध्यात्मिक पुरूष ही नहीं, कर्मयोगी भी थे। श्रीअरविंद का विचार था कि सिर्फ स्वतंत्रता भारत के लिए पर्याप्त नहीं होगी, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए। इसी अवधारणा को लेकर आज देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी वंदे मातरम के माध्यम से देश में पूर्ण स्वराज की स्थापना का उद्घोष कर रहे हैं। तोमर ने कहा कि भगवान ने बंकिम बाबू को वंदे मातरम लिखने की प्रेरणा दी और उसी अनुकंपा को आगे बढ़ाते हुए महर्षि अरविंद को भी अग्रसर किया।

तोमर ने कहा कि अतीत में वंदे मातरम पर आपत्ति का विरोध जोरदार ढंग से नहीं किया गया। जोरदार विरोध किया होता तो गीत का विभाजन नहीं होता और भारत का विभाजन नहीं होता। श्री तोमर ने संकल्प लेने का आव्हान करते हुए कहा कि जब तक पूर्ण वंदे मातरम साकार नहीं होगा कोई भी चैन से नहीं बैठेगा।

समारोह के अध्यक्षीय वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसंघ के क्षेत्र सहकार्यवाह हेमंत मुक्तिबोध ने अपने विचारोत्तेजक उद्बोधन में आह्वान किया कि हमें वंदे मातरम को साकार रूप में अंगीकार करना होगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का एक ही भाव है व्यक्ति के विचार, दृष्टि और कार्य समान होना चाहिए। वंदे मातरम ने करोड़ों लोगों में राष्ट्र वंदना की अलख जगाई। गीत में राष्ट्र भक्ति और अध्यात्म का अदभुत संगम है। गीत ने शताब्दी की दास्ता के खिलाफ जागरण का काम किया। यह गीत अतीत की स्मृति ही नहीं जागता बल्कि उज्जवल भविष्य का उद्घोष भी करता है।

मुक्तिबोध ने कहा कि संपूर्ण वंदे मातरम श्री अरविंद के भाव को व्यक्त करने वाला गीत है। यह बीज मंत्र है, देष भक्ति का, क्रांतिकारी का, नायक का, राजनीति, योगी और महर्षि का। भारत के उत्थान का अर्थ सनातन का उत्थान है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के एक चरण में जन है तो दूसरे चरण में मूल्य। हमें इस बात को समझना होगा कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि विभाजित गीत को अंगीकार करना पड़ा। यह खतरनाक है। इस गीत के संदर्भ में तीन बातें याद रखना जरूरी है। यह संपूर्ण गीत देश की एक सौ चालीस करोड़ जनता में आत्मबोध जगाने वाला गीत है।

श्रमिक मध्यप्रदेश के विकास की बुनियाद : डॉ. यादव

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 55 जिलों के 7,227 संबल हितग्राहियों के बैंक खातों में 160 करोड़ रुपये की अनुग्रह सहायता राशि अंतरित की

भोपाल, एजेंसी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि श्रमिक मध्यप्रदेश को गढ़ने वाले सच्चे सेवक हैं और उनकी मेहनत ही विकास की मजबूत बुनियाद है। राज्य सरकार हर परिस्थिति में श्रमिकों के साथ खड़ी है और जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री मंगलवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल 2.0) योजना के अंतर्गत सहायता राशि वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के 55 जिलों के 7,227 संबल हितग्राहियों के बैंक खातों में 160 करोड़ रुपये की अनुग्रह सहायता राशि अंतरित की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में योजना के प्रारंभ से अब तक 7.76 लाख प्रकरणों में 7,383 करोड़ रुपये की सहायता राशि जरूरतमंद हितग्राहियों को प्रदान की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबल योजना श्रमिकों के कठिन समय की सच्ची साथी है।

यह केवल आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं, बल्कि सरकार और श्रमिकों के बीच भरोसे का मजबूत रिश्ता है। समय के साथ श्रम के स्वरूप में आए बदलावों को देखते हुए सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को असंगठित श्रमिक का दर्जा दिया है और एक मार्च 2024 से उन्हें भी संबल योजना में शामिल किया गया है। अब तक 1,400 से अधिक गिग वर्कर्स का पंजीयन हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गरीबों और श्रमिकों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए संबल हितग्राहियों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया है, जिससे उन्हें 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज मिल रहा है। साथ ही 25 लाख से अधिक नए ई-श्रमिक परिवारों को राशन पात्रता प्रदान कर निःशुल्क राशन का लाभ दिया गया है। गर्भवती महिला श्रमिकों को 16 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है, ताकि वे गर्भावस्था के दौरान सुरक्षित रह सकें। उन्होंने कहा कि पत्थर तोड़ने वाले, ईंट भट्ठों में काम करने वाले, घरेलू श्रमिक, तेंदूपत्ता संग्राहक सहित सभी श्रमिक और उनके परिवार इस योजना से जुड़कर आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं। यह योजना आज श्रमिक परिवारों के लिए सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का भरोसा बन चुकी है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अमरकंटक से वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में शामिल होकर बताया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में संबल योजना के अंतर्गत सातवीं बार हितग्राहियों को राशि अंतरित की गई है। उन्होंने कहा कि योजना में अब तक 1.83 करोड़ से अधिक श्रमिकों का पंजीयन हो चुका है, जबकि संबल 2.0 में 43 लाख लोगों ने पंजीयन कराया है। अब किसी भी संबल प्रकरण में 60 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि संबल योजना के तहत महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता के रूप में 16 हजार रुपये दिए जाते हैं, श्रमिकों के बच्चों की उच्च शिक्षा का शिक्षण शुल्क राज्य सरकार वहन करती है और सभी पंजीकृत हितग्राही 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज प्राप्त कर रहे हैं। यह योजना आज श्रमिक परिवारों के लिए सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का भरोसा बन चुकी है।

गहलोत का अरावली के संबंधी में दिए फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह

जयपुर,एजेंसी।

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने उच्चतम न्यायालय से आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को देखते हुए अरावली के संबंध में दिए अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया हैं। गहलोत ने मंगलवार को अपने बयान में कहा कि केंद्र सरकार ने न्यायालय में ऐसी रिपोर्ट पेश की है जिससे अरावली का दायरा सिमट गया है। अरावली राजस्थान का केवल पर्वत नहीं, हमारा 'रक्षा कवच' है।

केंद्र सरकार की सिफारिश पर इसे 'सौ मीटर' के दायरे में समेटना, प्रदेश की 90 प्रतिशत अरावली के 'मृत्यु प्रमाण पत्र' पर हस्ताक्षर करने जैसा है।सबसे भयावह तथ्य यह है कि राजस्थान की 90 प्रतिशत अरावली पहाड़ियाँ 100 मीटर से कम हैं। यदि इन्हें परिभाषा से बाहर कर दिया गया, तो यह केवल नाम बदलना नहीं है बल्कि कानूनी कवच हटाना है।

इसका सीधा मतलब है कि इन क्षेत्रों में अब वन संरक्षण अधिनियम लागू नहीं होगा और खनन बेरोकटोक हो सकेगा। उन्होंने कहा कि पहाड़ की परिभाषा उसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि उसकी भूगर्भीय संरचना से होती है। एक छोटी चट्टान भी उसी टेक्टोनिक प्लेट और पर्वतमाला का हिस्सा है जो एक ऊंची चोटी है। इसे अलग करना वैज्ञानिक रूप से तर्कहीन है।

अरावली थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली दीवार है। विशेषज्ञों की चेतावनी है कि 10 से 30 मीटर ऊंची छोटी पहाड़ियां (रिज) भी धूल भरी आंधियों को रोकने में उतनी ही कारगर होती हैं। इन छोटी पहाड़ियों को खनन के लिए खोल देने का मतलब दिल्ली और पूर्वी राजस्थान तक रेगिस्तान को खुद निमंत्रण देना है। अरावली की चट्टानी संरचना बारिश के पानी को रोकती है और उसे जमीन के भीतर भेजती है। ये पहाड़ियाँ पूरे क्षेत्र में भूजल रिचार्ज का काम करती हैं।

इन्हें हटाने का मतलब पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे उत्तर-पश्चिम भारत में सूखे को निमंत्रण देना है। अरावली वह दीवार है जो पश्चिम से आने वाली जानलेवा 'लू' और थार रेगिस्तान को पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदानों में घुसने से रोकती है। उन्होंने कहा कि यह फैसला पर्यावरण संरक्षण नहीं, बल्कि खनन माफियाओं के लिए 'रेड कार्पेट' है।

सार समाचार

उत्तराखंड में शराब के दामों में नहीं होगी वृद्धि, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

नैनीताल,एजेंसी। उत्तराखंड में शराब (विदेशी मदिरा) के दाम में वृद्धि के मामले में राज्य सरकार को मंगलवार को उच्च न्यायालय से जोर का झटका लगा। उच्च न्यायालय ने दाम बढ़ाने वाली प्रदेश सरकार की अधिसूचना पर स्थगनादेश जारी कर दिया है। इस मामले को उत्तराखंड की प्रमुख शराब बनाने वाली डिस्टलरी मैसर्स इंडियन ग्याइकोल्स लिमिटेड की ओर से चुनौती दी गयी थी। साथ ही इस प्रकरण पर सुनवाई न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रदेश सरकार ने विगत 28 नवम्बर को एक अधिसूचना जारी कर प्रदेश में शराब के दामों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार आबकारी वर्ष (एक्साइज एयर) के मध्य में शराब के दामों में वृद्धि नहीं कर सकती है। आगे कहा गया कि अधिसूचना के माध्यम से उत्तराखंड आबकारी नीति विषयक नियमावली में संशोधन नहीं किया जा सकता है। संशोधन के लिये वही प्रक्रिया अपनानी होगी जो कि नियमावली बनाने अथवा तैयार करने के लिये अपनायी जाती है।

कर्नाटक के भटकल तहसीलदार कार्यालय में बम की धमकी से दहशत

भटकलएजेंसी। कर्नाटक में भटकल तहसीलदार के कार्यालय में ईमेल के ज़रिए बम की फर्जी धमकी मिलने से मंगलवार को दहशत फैल गई, जिसके बाद अधिकारियों ने सुरक्षा कड़ी कर दी और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष दस्ते तैनात किए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आज सुबह करीब 07:25 बजे मिले धमकी भरे ईमेल में कन्नड़ में लिखा था। तमिल और पाकिस्तानियों का बदलाः तहसीलदार के कार्यालय में जल्द ही एक शक्तिशाली बम फटेगा। सभी को जल्दी से बाहर निकालो। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने तुरंत आपातकालीन प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिए।

राउत ने चुनाव आयोग पर लगाया भेदभाव का आरोप

मुंबई,एजेंसी। शिवसेना (यूबीटी) नेता एवं राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने सरकार और चुनाव आयोग पर आदर्श आचार संहिता को चुनिंदा तरीके से लागू करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि इसे सिर्फ मराठी लोगों और विपक्षी पार्टियों के खिलाफ लागू किया जा रहा है। राउत ने मंगलवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पिछले कुछ दिनों में मुंबई में 'मुंबई को बचाने' और 'मराठी पहचान को बनाए रखने' के लिए लगाए गए पोस्टर सरकार ने एमसीसी के उल्लंघन का हवाला देते हुए डर के मारे हटा दिए हैं। उन्होंने सवाल किया, क्या एमसीसी सिर्फ मराठी लोगों और विपक्ष पर लागू होता है? सरकार के अपने लोगों पर नहीं? राउत ने आरोप लगाया कि धन और शहरी विकास से जुड़े सरकारी आदेश चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से ठीक 10 मिनट पहले तक जारी किए गए थे।

हमारी सरकार ने समृद्ध एवं विकसित राजस्थान की रखी सशक्त बुनियाद : मुख्यमंत्री भजनलाल

बीकानेर, एजेंसी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार गरीब को गणेश मानकर सेवक के रूप में कार्य कर रही है। हमारा नैतिक दायित्व है कि हम सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखें। हमारी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में बजट दिया और हर विधानसभा क्षेत्र में विकास रथ के माध्यम से विकास कार्यों का लेखा-जोखा जनता तक पहुंचा रही है। शर्मा मंगलवार को बीकानेर के लूणकरणसर में ग्रामीण समस्या समाधान शिविर एवं बीकानेर जिले के विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने दो वर्षों में प्रदेश में सुशासन, जनकल्याण और चहुंमुखी विकास के लिए ऐसे अभूतपूर्व कदम उठाए हैं, जो ऐतिहासिक होने के साथ ही समृद्ध एवं विकसित राजस्थान की एक सशक्त बुनियाद भी हैं।

शर्मा ने कहा कि जनसेवा के भाव के साथ ग्रामीण एवं शहरी समस्या समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस पर 17 सितंबर से प्रदेश भर में एक महीने तक ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया था। इन शिविरों में प्रशासन को आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए उनके द्वार तक लाया जा रहा है। शहरी शिविरों के जरिए जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीकरण, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस और सीवर कनेक्शन से जुडे. कार्यों से लेकर आवास पट्टे, नामांतरण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ने संबंधी कार्य भी करवाए जा रहे हैं। वहीं, ग्रामीण समस्या समाधान शिविरों में सहमति विभाजन, नामांतरण एवं रास्ते खुलवाने जैसे कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने आह्वान किया कि आमजन इन शिविरों का पूरा लाभ उठाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने किसान, युवा, महिला और गरीब के उत्थान के लिए कई कदम उठाए हैं। हमने किसानों के लिए सम्मान निधि को 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार रुपये किया गया है तथा चरणबद्ध रूप से इसे 12 हजार रुपये किया जाएगा।

इसी तरह हमारी सरकार ने इन दो वर्षों में युवाओं के लिए सरकारी सेवाओं में अवसर बढ़ाते हुए लगभग 92 हजार नियुक्तियां प्रदान की है तथा 1 लाख 56 हजार पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है। वहीं, प्रदेश में 12 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाने से लेकर 10 लाख 51 हजार साइकिलें और करीब 40 हजार स्कूटियां वितरण एवं लाडो प्रोत्साहन योजना की पहली किस्त से 4 लाख 60 हजार बालिकाओं को लाभांवित करने का काम किया गया है।

आगामी फरवरी में साहसिक खेलों से गूंजेगी नयार घाटी

पौड़ी,एजेंसी। उत्तराखंड में पौड़ी जिले की नयार घाटी फरवरी, 2026 में साहसिक खेल गतिविधियों का बड़ा केंद्र बनने जा रही है। सतपुली क्षेत्र के बिलखेत में 26 से 28 फरवरी तक तीन दिवसीय नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल–2026 का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पैराग्लाइडिंग, क्याकिंग, साइक्लिंग और एंग्लिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों से पूरी नयार घाटी साहसिक खेलों और उत्साह से गूंज उठेगी। इस महोत्सव का आयोजन जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग एवं मत्स्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। हाल ही में जिलाधिकारी के निर्देशन में पर्यटन विभाग द्वारा बिलखेत में पैराग्लाइडिंग का सफल ट्रायल किया गया था। ट्रायल की सफलता के बाद अब तीन दिवसीय महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल के अंतर्गत लैंसडाउन, खिर्सू और बिलखेत में साइक्लिंग रैली का आयोजन किया जाएगा।

मनरेगा में 47 करोड़ रुपये के 3680 कार्य स्वीकृत

बीजापुर,एजेंसी।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत ग्रामीण श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुल 47 करोड़ रुपये की लागत से 3680 विकासात्मक कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्यों के माध्यम से जरूरतमंद एवं पंजीकृत श्रमिक परिवारों को अपने गांव में ही रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे पलायन पर रोक लगेगी।

मंगलवार को जिला पीआरओ से मिली जानकारी के मुताबिक,विकासखंडवार स्वीकृत कार्यों की संख्या इस प्रकार है- बीजापुर विकासखंड में 691, भैरमगढ़ में 1266, भोपालपटनम में 952 तथा उसूर विकासखंड में 771 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। जिले में पर्याप्त मात्रा में कार्य स्वीकृत होने से अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ी है। वर्तमान में मनरेगा अंतर्गत मजदूरी दर 261 रुपये प्रतिदिन निर्धारित है।जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि श्रमिकों को समयबद्ध रूप से कार्य उपलब्ध हो तथा मजदूरी का भुगतान पारदर्शी तरीके से निर्धारित समय सीमा में किया जाए। मनरेगा योजना के तहत जल संरक्षण एवं जनहितकारी कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है।

खेल के मैदान में बह रहा खिलाड़ियों का खून, सरकार सुरक्षा देने में विफल: खन्ना

चंडीगढ़,एजेंसी।

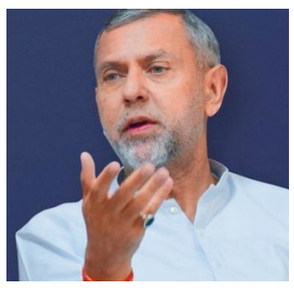

पंजाब भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अरविंद खन्ना ने मंगलवार को मौजूदा सरकार को कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर घेरते हुए कहा है कि पंजाब वासियों को रंगला पंजाब का सपना दिखाने वाली आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार खिलाड़ियों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। खन्ना ने पंजाब के मोहाली में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ी राणा बलाचौरिया की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि पंजाब सरकार पिछले करीब चार वर्षों के दौरान खिलाड़ियों को सुरक्षा देने में विफल रही है।

उन्होंने कहा कि साल 2022 में नकोदर में संदीप नंगल अंबियां, इस साल के दौरान अक्टूबर में जगरांव में तेजपाल सिंह, नवंबर में लुधियाना में गुरविंदर सिंह और अब दिसंबर में मोहाली में राणा बलाचौरिया की हत्या से खिलाड़ियों तथा खेल प्रेमियों में भारी रोष पाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कबड्डी व कुश्ती पंजाब की खुशहाली का प्रतीक रहे हैं लेकिन पिछले तीन वर्षों से न तो खिलाड़ी सुरक्षित हैं और न ही खेल प्रेमी सुरक्षित हैं। खन्ना ने कहा कि मोहाली में राणा बलाचौरिया की हत्या के दौरान सैकड़ों की संख्या में खेल प्रेमियों की भीड़ मौजूद थी। हमलावर भीड़ में आम जनता को भी निशाना बना सकते थे। इतने बड़े आयोजन में कम पुलिस बल की तैनाती सरकार की बड़ी असफलता है। पंजाब में आए दिन हो रही घटनाओं से खेल प्रेमियों में भारी रोष पाया जा रहा है।

आंध्र सरकार स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची मूर्ति लगाएगी

विजयवाड़ा,एजेंसी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को अमरावती में अमरजीवी पोट्टी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची मूर्ति बनाने की घोषणा की, जिसका नाम 'बलिदान की मूर्ति' रखा जाएगा।

विजयवाड़ा के तुम्मलपल्ली कलाक्षेत्रम में आयोजित पोट्टी श्रीरामुलु आत्मार्पण दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने पोट्टी श्रीरामुलु के परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया और उनकी विरासत को याद करने के लिए कई पहलों की रूपरेखा बताई। उन्होंने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी को सम्मान देने के लिए 6.5 एकड़ में एक मेमोरियल पार्क भी बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि वासावी कन्याकापरमेश्वरी के जन्मस्थान पेनगोंडा का नाम बदलकर 'वासावी पेनगोंडा' किया जाएगा और एक विशाल मंदिर बनाया जाएगा।

मणिपुर में हथियारों का बड़ा जखीरा जब्त, उग्रवादी और ड्रग तस्कर गिरफ्तार

इम्फाल,एजेंसी।

मणिपुर में प्रतिबंधित विद्रोही समूहों और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने अभियान तेज कर दिया है। इसके तहत सोमवार को कई स्थानों से भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक बरामद किए गये तथा प्रतिबंधित संगठन के सक्रिय सदस्यों एवं एक मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि थौबल जिले में सुरक्षा बलों ने खोंगजोम थाने के तहत टेंथा तुवाबंद इरेल चिंग इलाके से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं।

इनमें तीन 12 बोर राइफल, मैगजीन सहित एक एसएमजी कार्बाइन, एक मॉडिफाइड .303 राइफल, एक मॉडिफाइड .32 पिस्टल, दो 36 एचई हैंड ग्रेनेड, इंसास एलएमजी और एसएलआर के मैगजीन, विभिन्न कैलिबर की गोलियां, दंगा रोधी रबर बुलेट के खोल और आंसू गैस के गोले शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि इम्फाल पश्चिम जिले के सागोलमांग पुलिस थाने के तहत चैनुंग पहाड़ी श्रृंखला क्षेत्र से भी सुरक्षा बलों ने हथियार और गोला-बारूद जब्त किया जिनमें मॉडिफाइड और गैर मॉडिफाइड .303 राइफलें।

12 बोर एसबीबीएल बंदूकें, स्थानीय स्तर पर बनी एसबीबीएल बंदूकें, इंसास एलएमजी और राइफल के मैगजीन, इंसास, .303 और 7.62 मिमी कैलिबर के जिंदा कारतूस, बिना डेटोनेटर का एक हैंड ग्रेनेड, एक 2 इंच का एचई मोर्टार शेल, और दो बुलेटप्रूफ जैकेट के कवर शामिल हैं। सागोलमांग पुलिस थाने के तहत चंगसांग पहाड़ी श्रृंखला क्षेत्र से भी मैगजीन सहित एक देशी 9 मिमी पिस्टल, जिंदा गोलियां।

विभिन्न राइफलों के कारतूस, इंसास एलएमजी के मैगजीन, एके और एसएलआर राइफल के फायर किए गए कारतूस केस और एक पिस्टल होल्स्टर बरामद किये गये। इस बीच, सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान के दौरान प्रतिबंधित विद्रोही समूहों के कई सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया। इम्फाल पश्चिम जिले में इम्फाल थाने के तहत कीशमपत कोंजेंग हजारी लीकाई से एक ग्रुप के एक सक्रिय सदस्य को हिरासत में लिया गया।

एक अन्य अभियान में कामजोंग जिले के मुइरी गांव के सुइमी अवुंगशी को एक किलो ब्राउन शुगर के साथ लमलई थाने के तहत सावोमबंग तेजपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

वही, उसी दिन इम्फाल पश्चिम और बिष्णुपुर थाने के तहत लोकतक प्रोजेक्ट गेट क्षेत्र से एक प्रतिबंधित समूह के सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा एक प्रतिबंधित समूह के सब-सेक्शन सार्जेंट को हेइरांगोइथोंग इलाके से गिरफ्तार किया गया।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सात निश्चय-3 के प्रभावी क्रियान्वयन से विकसित बिहार का संकल्प पूरा होगा

नीतीश कैबिनेट बैठक में सात निश्चय योजना 3.0 को मंजूरी

पटना, एजेंसी।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में सात निश्चय योजना 3.0 को मंजूरी दे दी गई। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जानकारी साझा की।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 24 नवंबर 2005 से राज्य में कानून का राज स्थापित है। सुशासन के कार्यक्रमों के तहत सात निश्चय (2015-2020) और सात निश्चय-2 (2020-2025) के निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया गया है। अब बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के उद्देश्य से सात निश्चय-3 को लागू करने का निर्णय लिया गया है।

सात निश्चय-3 का पहला निश्चय 'दोगुना रोजगार-दोगुनी आय' है। इसका उद्देश्य राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करना है। इसके तहत 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10 हजार रुपये दिए जाएंगे ।

दूसरा निश्चय 'समृद्ध उद्योग-सशक्त बिहार' है। इसके तहत औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया गया है। अगले पांच वर्षों में राज्य में कम से कम 50 लाख करोड़ रुपये के निजी निवेश का लक्ष्य तय किया गया है।

तीसरा निश्चय 'कृषि में प्रगति-प्रदेश की समृद्धि' है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए वर्ष 2024 से 2029 तक के चौथे कृषि रोड मैप के कार्यों में तेजी लाई जाएगी। मखाना रोड मैप बनाकर मखाना के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा।

चौथा निश्चय 'उन्नत शिक्षा-उज्ज्वल भविष्य' है। इसके तहत राज्य में अलग उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया गया है।

पांचवां निश्चय 'सुलभ स्वास्थ्य-सुरक्षित जीवन' है। प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र और जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

छठा निश्चय 'मजबूत आधार-आधुनिक विस्तार' है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों का विस्तार, नागरिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण और नए नियोजित शहरों का विकास किया जाएगा। 5 नई एक्सप्रेस-वे सड़कों का निर्माण, ग्रामीण सड़कों का दो लेन में चौड़ीकरण, सोलर ऊर्जा को बढ़ावा और पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। साथ ही फिल्म सिटी का निर्माण कर फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

सातवां और अंतिम निश्चय 'सबका सम्मान-जीवन आसान' है। इसके तहत आधुनिक तकनीक, नवाचार और संवेदनशील सुशासन के माध्यम से राज्य के नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर जोर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सात निश्चय-3 के प्रभावी क्रियान्वयन से विकसित बिहार का संकल्प पूरा होगा और बिहार देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा।

ममता ने खेल मंत्री अरूप विश्वास का इस्तीफा स्वीकार किया

कोलकाता,एजेंसी।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को राज्य के खेल मंत्री अरूप विश्वास का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। उल्लेखनीय है कि विश्वास ने फुटबॉलर लियोनेल मेसी के स्वागत कार्यक्रम के दौरान पिछले हफ्ते सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई तोड़फोड़ की स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए मंगलवार को ही अपना इस्तीफा सौंपा था।

विश्वास को इस दुर्घटना के कारण विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। इस घटना की जांच के लिए मुख्यमंत्री ने कोलकात्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश असीम कुमार रॉय की अध्यक्षता में जांच दल गठित किया है।

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने श्री विश्वास का अनुरोध स्वीकार करते हुए उन्हें खेल विभाग से मुक्त कर दिया। फिलहाल सुश्री बनर्जी खेल विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगी। इस बीच विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को श्री विश्वास के साथ-साथ अग्निशमन सेवा मंत्री सुजीत बोस की गिरफ्तारी की अपनी मांग दोहराई। उन्होंने स्टेडियम में हुई अराजकता के लिए दोनों को जिम्मेदार ठहराया।

भारत की नजरें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला जीतने पर

अक्षर पटेल बीमारी के कारण श्रृंखला से बाहर,भारत ने शाहबाज अहमद को टीम में शामिल किया है

लखनऊ,एजेंसी। शुभमन गिल का खराब प्रदर्शन चर्चा का विषय बना हुआ है लेकिन साथ ही खराब फॉर्म से जूझे रहे कप्तान सूर्यकुमार यादव भी समीक्षा के दायरे में हैं क्योंकि भारत बुधवार को यहां चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में सही संतुलन तलाश कर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैच की श्रृंखला में विजयी बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगा। तीसरे मैच में सूर्यकुमार के पास वह लय हासिल करने का अच्छा मौका था जिसने उन्हें दुनिया का शीर्ष बल्लेबाज बनाया था क्योंकि भारत 118 रन के मामूली लक्ष्य का पीछा किया कर रहा था लेकिन उन्होंने यह मौका गंवा दिया और सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए।

एक समय उनका दबदबा स्थापित करने वाले शॉट अनियमित परिणाम दे रहे हैं और धर्मशाला में मैच भी अलग नहीं था क्योंकि वह अपना चिर-परिचित पिक-अप शॉट खेलते हुए आउट हुए जो उनके निरंतर संघर्ष को उजागर करता है।

सूर्यकुमार ने हालांकि कहा कि वह खराब फॉर्म से नहीं जूझ रहे। उन्होंने रविवार को धर्मशाला में भारत की जीत के बाद कहा, मैं नेट में शानदार बल्लेबाजी कर रहा हूं। मैं वह सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं जो मेरे नियंत्रण में है। जब रन आने होंगे तो वे निश्चित रूप से आएंगे। मैं खराब फॉर्म से नहीं जूझ रहा लेकिन निश्चित तौर पर रन नहीं बना पा रहा।

हालांकि आंकड़े एक चिंताजनक कहानी बताते हैं। भारतीय कप्तान एक साल से अधिक समय से लय हासिल करने के लिए जूझ रहे हैं। मौजूदा सत्र में इस प्रारूप में उनका औसत 15 से कम है। इसके अलावा 2025 में उनके नाम कोई अर्धशतक नहीं है जो उनके करियर में इस तरह का सबसे लंबा चरण है। वह इस दौरान केवल दो बार 20 गेंद से अधिक बल्लेबाजी करने में सफल रहे हैं। टी20 विश्व कप में दो महीने से भी कम समय बचा है और ऐसे में गत चैंपियन टीम चाहेगी कि उनका कप्तान और प्रमुख बल्लेबाज जल्द से जल्द लय फिर से हासिल कर ले। उप कप्तान शुभमन गिल का प्रदर्शन भी काफी खराब रहा है। उनके पारी का आगाज करने से भारत का शीर्ष क्रम अस्थिर हो गया है।

गिल ने अच्छी तरह से स्थापित संजू सैमसन की जगह ली। केरल के विकेटकीपर बल्लेबाज को अभिषेक शर्मा के साथ एक प्रभावी साझेदारी बनाने के बावजूद पहले निचले क्रम में धकेल दिया गया और अंततः बाहर कर दिया गया।

गिल ने अन्य प्रारूपों में अपना स्तर दिखाया है लेकिन टी20 अंतरराष्ट्रीय में उन्हें अब भी उस आश्वस्त बल्लेबाज की झलक नहीं दिखाई है जो वह टेस्ट और एकदिवसीय में है। वह रविवार को कम लक्ष्य का पीछा करते हुए भी सिर्फ 28 रन ही बना पाए जिसने विश्व कप से पहले चिंताओं को कम नहीं किया है। विश्व कप से पहले भारत के पास इस प्रारूप में अब सिर्फ सात मैच हैं।

मेस्सी ने देखा भारतीय फुटबॉल का बेशर्म चेहरा

राजेंद्र सजवान

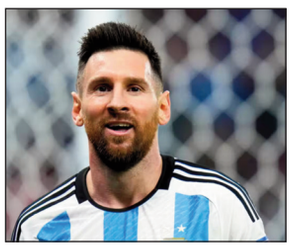

फुटबॉल जगत के महानतम खिलाड़ियों में शुमार लियोनेल मेस्सी के भारत दौरे से भारतीय फुटबॉल को क्या मिला? यह सवाल देश के आम फुटबॉलर, फुटबॉल प्रेमियों और जागरूक नागरिकों द्वारा पूछा जा रहा है। भले ही बेंगलुरू, मुम्बई और दिल्ली में कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ लेकिन भारतीय फुटबॉल का मक्का कहलाने वाले शहर कोलकाता में जो कुछ हुआ बेहद शर्मनाक था। सॉल्टलेक स्टेडियम में तोड़फोड़ की तस्वीरें पूरी दुनिया में थू-थू अर्जित कर रही है।

अब सवाल यह किया जा रहा है कि जब मेस्सी को आम फुटबॉल प्रेमियों के सामने आना ही नहीं था तो उन्हें क्यों बुलाया गया और भारतीय फुटबॉल को मेस्सी के आने से क्या हासिल हुआ? यह जगजाहिर है कि भारत फुटबॉल में सबसे फिसड्डी देश है क्योंकि दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल में जिस खेल भावना और शालीनता की जरूरत है, भारतीय फुटबॉल उसके आस-पास भी नहीं है।

भ्रष्टाचार, व्यभिचार, उम्र की धोखाधड़ी, फिक्सिंग, सट्टेबाजी और तमाम बुराइयां दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की रग-रग में समाई है, जो कि मेस्सी के आने पर खुलकर सामने आ गई। फुटबॉल पागलों और मेस्सी के दीवानों से 10 से 20 हजार लूटे गए, लाखों में मेस्सी से नजदीकी को बेचा गया लेकिन हजारों फुटबॉल प्रेमी ठगे रह गए। इसलिए क्योंकि सुपर स्टार देश के लुटेरे, नंग और फुटबॉल का बलात्कार करने वाले नेताओं और अमीरों से घिरा हुआ था।

हालांकि लूट का खेल बेंगलुरू, मुम्बई और दिल्ली में भी खेला गया लेकिन अफरा-तफरी, लूट-खसोट और तोड़-फोड़ पर नियंत्रण रखा गया। फिर भी एक सवाल पूछा जा रहा है कि दिल्ली के फिरोजशाह कोटला (अब अरुण जेटली स्टेडियम) क्रिकेट स्टेडियम में मेस्सी का स्वागत सत्कार क्यों किया गया, जबकि बगल में डॉ बीआर अम्बेडकर स्टेडियम फुटबॉल का मैदान है। कुछ नाराज फुटबॉल प्रेमियों को लगता है कि उनके खेल को हैसियत का आईना दिखा दिया गया है।

कुल मिलाकर मेस्सी के दौरे को सरकार और मेजबान शहरों की राज्य सरकारें भले ही अपनी उपलब्धि बताएं लेकिन देश का आम और खास फुटबॉल प्रेमी और पूर्व खिलाड़ी कह रहे हैं कि मेस्सी के दौरे से भारतीय फुटबॉल पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। फुटबॉल के पागल शहर कोलकाता की शर्मनाक हरकतों और फुटबॉल के लुटेरों की देशद्रोही गतिविधियों से साफ हो गया है कि हम कभी सबसे बड़े और लोकप्रिय खेल में नाम-सम्मान नहीं कमा सकते हैं।

आईपीएल का 19वां सत्र 26 मार्च से 31 मई तक होगा

मुंबई,एजेंसी। इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सत्र का आयोजन 26 मार्च से 31 मई तक किया जाएगा लेकिन यह देखना होगा कि भगदड़ में लोगों की मौत के कारण एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सभी बड़े क्रिकेट आयोजन रुकने के बाद गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के घरेलू मैदान को मेजबानी का मौका मिलता है या नहीं। स्थापित नियमों के अनुसार एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को टूर्नामेंट के पहले मैच की मेजबानी का मौका मिलना चाहिए क्योंकि घरेलू टीम आरसीबी ने आईपीएल 2025 का खिताब जीता था लेकिन जब तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) पूर्ण कार्यक्रम जारी नहीं करता तब तक स्थति स्पष्ट होने की संभावना नहीं है।

इस साल जून में आरसीबी के जीत के जश्न के दौरान सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ जुटने के बाद आयोजन स्थल पर अराजकता और भगदड़ मच गई थी जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि आयोजन स्थल को कर्नाटक सरकार से सशर्त मंजूरी मिल गई है लेकिन मौतों के बाद इसे आवश्यक सुरक्षा मानकों को पूरा करने की भी आवश्यकता है। सरकारी एजेंसियों से अपेक्षित मंजूरी के बिना लोगों को सड़क पर जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए फ्रेंचाइजी की कड़ी आलोचना हुई थी। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद ने मैसूरु में कहा, हर साल आईपीएल का उद्घाटन मैच पारंपरिक रूप से उस टीम के घरेलू मैदान पर होता है जिसने पिछले सत्र में ट्रॉफी जीती थी।

उन्होंने कहा, लेकिन चार जून को आरसीबी के आईपीएल चैंपियनशिप जश्न के दौरान भगदड़ के कारण कुछ अनिश्चितता थी इसलिए मैंने बेंगलुरु में उद्घाटन मैच की मेजबानी के बारे में बीसीसीआई के साथ चर्चा की है।

कुंडू का दोहरा शतक, भारत ने मलेशिया को 315 रन से हराया

दुबई,एजेंसी। अभिज्ञान कुंडू के दोहरे शतक (209) और दीपेश देवेंद्रन (22/5) के पांच विकेटों की बदौलत मंगलवार को यहां अंडर-19 एशिया कप 2025 के मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 315 रन से मात दी। भारतीय युवाओं ने मलेशिया के सामने 50 ओवर में 409 रन का लक्ष्य रखा। इसके जवाब में मलेशियाई टीम 32.1 ओवर में 93 रन पर ऑलआउट हो गयी। मलेशिया की ओर से हमज़ा पंगी ने सर्वाधिक 35 रन बनाये।

मलेशिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करते हुए कप्तान और सलामी बल्लेबाज आयुष म्हात्रे को 14 रन पर पवेलियन लौटा दिया। तीसरे नंबर पर बल्लेबाज़ी करने उतरे विहान मल्होत्रा भी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाये और सात रन बनाकर पवेलियन लौट गये, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने वेदांत त्रिवेदी के साथ मिलकर पारी को संभाल लिया। त्रिवेदी ने पहले सूर्यवंशी के साथ मिलकर 40 रन जोड़े। इसके बाद उन्हें कुंडू का साथ मिला और दोनों ने चौथे विकेट के लिये 181 गेंदों पर 209 रन जोड़कर मलेशियाई गेंदबाज़ी की कमर तोड़ दी।

त्रिवेदी 106 गेंदों पर सात चौकों के साथ 90 रन बनाकर अपने शतक से चूक गये, जबकि कुंडू ने 80 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। मैच के अंतिम ओवरों में कुंडू ने आक्रामक बल्लेबाजी कर न सिर्फ भारत को 400 रन के पार पहुंचाया, बल्कि यूथ एकदिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले पहले भारतीय भी बन गये। इस 17 वर्षीय खब्बू बल्लेबाज ने 125 गेंद पर 17 चौकों और नौ छक्कों के साथ 209 रन बनाये। इससे पहले यूथ वनडे में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले भारतीय वैभव सूर्यवंशी थे, जिन्होंने इसी टूर्नामेंट में यूएई के खिलाफ पिछले मैच में 171 रन बनाये थे।

कुंडू ने 44 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और सिर्फ 80 गेंदों में शतक जड़ डाला। वह 46वें ओवर में 150 रन तक पहुंचे और फिर रफ्तार पकड़कर 49वें ओवर में 121 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया। उन्होंने कनिष्क चौहान के साथ 36 गेंदों में 87 रनों की तूफानी साझेदारी करके भारत को 50 ओवर में सात विकेट पर 408 रन बनाने में मदद की। कुंडू का स्कोर अंडर-19 क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के जोरिक वैन शाल्कविक के 215 रनों के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है।

यह अंडर-19 एशिया कप में किसी भी खिलाड़ी का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मलेशियाई टीम ने भारतीय गेंदबाजी के सामने घुटने टेक दिये। देवेंद्रन ने सात ओवर में 22 रन देकर पांच विकेट लिये, जबकि उधव मोहन ने 24 रन देकर दो विकेट चटकाये। किशन कुमार सिंह, खिलन पटेल और चौहान ने एक-एक विकेट चटकाया।

एरिना सबालेंका फिर डब्ल्यूटीए की साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनीं

न्यूयॉर्क,एजेंसी। एरिना सबालेंका ने सोमवार को लगातार दूसरी बार डब्ल्यूटीए की साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। उन्हें अमेरिकी ओपन जीतने, दो अन्य ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने और सत्र का अंत नंबर एक खिलाड़ी के रूप में करने के लिए मीडिया पैनल से लगभग 80 प्रतिशत वोट मिले। सबालेंका पिछले 25 वर्षों में सेरेना विलियम्स और इगा स्वियातेक के साथ लगातार दो बार यह सम्मान जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। बेलारूस की 27 साल की सबालेंका 2025 में महिला टेनिस में मैच जीतने (63 जीत, 12 हार), खिताब जीने (चार) और फाइनल में पहुंचने (नौ) में सबसे आगे रहीं।

उन्होंने एक करोड़ 50 लाख डॉलर की इनामी राशि जीतकर टूर रिकॉर्ड बनाया। वह पूरे साल नंबर एक खिलाड़ी रहीं।

सबालेंका जनवरी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन के फाइनल में मेडिसन कीज से और जून में फ्रेंच ओपन के फाइनल में कोको गॉफ से हार गईं थी। वह जुलाई में विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंचीं और फिर सितंबर में अमेरिकी ओपन के फाइनल में अमांडा अनिसिमोवा को हराकर अपने करियर की चौथी ग्रैंड स्लैम एकल ट्रॉफी जीती। अमेरिका की 24 साल की अनिसिमोवा को विंबलडन और अमेरिकी ओपन के फाइनल में पहुंचने के लिए सबसे अधिक सुधार करने वाली खिलाड़ी चुना गया।

बिजनेस

पोको सी85 5जी की पहली सेल शुरू

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत के सबसे भरोसेमंद कंज्यूमर टेक्नोलॉजी ब्रांड्स में से एक पोको ने अपने बिल्कुल नए पोको सी85 5जी की पहली सेल शुरू कर दी है, जो खास तौर पर फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। सबसे अच्छे बैटरी एक्सपीरियंस के लिए, पोको सी85 5जी में 6000एमएएच की बैटरी है जो दो दिन से ज्यादा चलती है।

भारत का कम्पोजिट पीएमआई दिसंबर में 58.9 रहा

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत का कम्पोजिट पीएमआई दिसंबर में 58.9 रहा है, जो दिखाता है कि देश में व्यापारिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई है। यह जानकारी दिसंबर के एचएसबीसी फ्लैश इंडिया पीएमआई डेटा में मंगलवार को दी गई। जब भी पीएमआई 50 से ऊपर होता है, तो यह वृद्धि को दिखाता है।

पीएम सूर्य घर योजना से 7.7 लाख से ज्यादा घरों को राहत, बिजली बिल हुआ शून्य

नई दिल्ली,एजेंसी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना देश में घरों की बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला रही है। इस योजना के तहत अब तक देश के 7.7 लाख से अधिक घरों का बिजली बिल शून्य हो गया है। इस योजना के अंतर्गत घरों में छत पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को बिजली बिल से निजात मिल रही है। यह जानकारी मंगलवार को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने दी।

फरवरी 2024 में शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को सस्ती और साफ ऊर्जा उपलब्ध कराना एवं उनके घरों का बिजली खर्च कम करना है। साथ ही, यह योजना देश को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। राज्यसभा में जानकारी साझा करते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कहा कि 9 दिसंबर तक पूरे देश में 19,45,758 रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। इन सोलर सिस्टम से 24,35,196 परिवारों को लाभ मिला है।

इनमें से लाखों परिवार ऐसे हैं, जिनका बिजली बिल अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। इस योजना का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 तक देश के एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाना है। इसके लिए सरकार ने 75,021 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। इस योजना का उद्देश्य ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, बिजली के बिल को कम करना और देश के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में सहयोग करना है।

मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, इस योजना में गुजरात सबसे अग्रणी राज्य बनकर उभरा है, जहां अब तक 4.93 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे 7.10 लाख से ज्यादा परिवारों को फायदा हुआ है। इनमें से 3.62 लाख घरों का बिजली बिल पूरी तरह शून्य हो गया है। गुजरात के अलावा आंध्र प्रदेश, असम और हरियाणा जैसे राज्यों में भी इस योजना के तहत अच्छी प्रगति देखने को मिल रही है।

इन राज्यों में हजारों परिवारों ने अपने घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगवाए हैं और अब वे सस्ती और स्वच्छ बिजली का उपयोग कर रहे हैं। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सोलर सिस्टम लगवाना आम लोगों के लिए आसान और सस्ता हो। इसके लिए केंद्र सरकार आर्थिक सहायता दे रही है और बिना गारंटी का सस्ता लोन भी उपलब्ध करा रही है। इस लोन पर ब्याज दर केवल 5.75 प्रतिशत रखी गई है, जिससे सोलर सिस्टम लगाने का शुरुआती खर्च कम हो जाता है।

कमजोर रुपये के दबाव में सेंसेक्स 533 अंक लुढ़का

मुंबई,एजेंसी। रुपये के लगातार दबाव में रहने से मंगलवार को घरेलू शेयर बाजारों में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखी गयी और बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 533.50 अंक (0.63 प्रतिशत) लुढ़ककर 84,679.86 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी-50 सूचकांक भी 167.20 अंक यानी 0.64 प्रतिशत गिरकर 25,860.10 अंक पर आ गया। यह दोनों सूचकांकों का 10 दिसंबर के बाद का निचला स्तर है। भारतीय मुद्रा आज पहली बार बीच कारोबार में 91 रुपये प्रति डॉलर से नीचे उतर गयी।

इससे निवेश धारणा कमजोर रही। चौतरफा बिकवाली के बीच सुबह से ही बाजार पर दबाव रहा। सेंसेक्स एक समय 597 अंक लुढ़क गया था। मझौली और छोटी कंपनियों पर भी दबाव देखा गया। निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.86 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.92 प्रतिशत की गिरावट में रहा। टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद और मीडिया को छोड़कर अन्य सभी सेक्टरों पर बिकवाली हावी रही। रियलिटी, बैंकिंग, वित्त, आईटी और धातु समूहों से सूचकांक ज्यादा टूटे।

बाजार पर दबाव इस कदर रहा कि एनएसई में जिन 3,211 कंपनियों के शेयरों में आज कारोबार हुआ उनमें से 2,095 के शेयर गिरकर बंद हुए। वहीं, 93 कंपनियों के शेयर अंततः अपरिवर्तित रहे। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 22 के शेयर लाल निशान में बंद हुए। एक्सिस बैंक में सबसे अधिक 5.03 प्रतिशत की गिरावट रही। इटरनल का शेयर 4.69 प्रतिशत से अधिक लुढ़क गया। एचसीएल टेक्नोलॉजीज का शेयर 1.90 प्रतिशत, टाटा स्टील का 1.74, बजाज फिनसर्व और अल्ट्राटेक सीमेंट दोनों के 1.65 और बजाज फाइनेंस का 1.41 प्रतिशत टूट गया।

रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफोसिस, एनटीपीसी, अडानी पोर्ट्स, सनफार्मा, टीसीएस, पावरग्रिड, बीईएल, एलएंडटी, भारतीय स्टेट बैंक और हिंदुस्तान यूनीलिवर के शेयर भी लाल निशान में रहे। टाइटन में 1.60 प्रतिशत की तेजी रही। भारती एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एशियन पेंट्स के शेयर भी बढ़त के साथ बंद हुए। अमेरिका में रोजगार के आंकड़ों से पहले वैश्विक स्तर पर शेयर बाजारों में गिरावट रही। एशिया में जापान का निक्केई 1.56 प्रतिशत, हांगकांग का हैंगसेंग 1.54 प्रतिशत और चीन का शंघाई कंपोजिट 1.11 प्रतिशत टूट गया।

रबी फसलों की बुवाई 536 लाख हेक्टेयर के पार, इस साल 24 लाख हेक्टेयर बढ़ा रकबा

नई दिल्ली। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि इस साल 5 दिसंबर तक रबी फसलों के तहत बोया गया कुल रकबा पिछले साल इसी अवधि के 512.76 लाख हेक्टेयर की तुलना में 24 लाख हेक्टेयर बढ़कर 536.76 लाख हेक्टेयर हो गया है। बोए गए रकबे में बढ़ोतरी से उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और खाद्य महंगाई को भी काबू में रखने में मदद मिलेगी।

आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि गेहूं का रकबा पिछले साल इसी अवधि के 258.48 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 17.18 लाख हेक्टेयर बढ़कर 275.66 लाख हेक्टेयर हो गया है।उड़द, मसूर और मूंग जैसी दालों के तहत रकबा पिछले साल इसी अवधि के 115.41 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 117.11 लाख हेक्टेयर हो गया है।ज्वार, बाजरा और रागी जैसे मोटे अनाज या बाजरा के तहत कवर किया गया रकबा पिछले साल इसी अवधि के 41.13 लाख हेक्टेयर की तुलना में मौजूदा सीजन में अब तक 0.64 लाख हेक्टेयर बढ़कर 41.77 लाख हेक्टेयर हो गया है।

सरसों और राई जैसी तिलहन फसलों के तहत रकबा पिछले साल इसी अवधि के 87.1 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2.7 लाख हेक्टेयर बढ़कर 89.79 लाख हेक्टेयर हो गया है।मौजूदा सीजन में बोया गया रकबा बढ़ा है क्योंकि बेहतर मानसून की बारिश ने बिना सिंचाई वाले क्षेत्रों में बुवाई को आसान बना दिया है, जो देश की कृषि भूमि का लगभग 50 प्रतिशत है।आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 1 अक्टूबर को 2026-27 मार्केटिंग सीजन के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दी जिससे उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।

न्यूनतम समर्थन मूल्य बुवाई के मौसम से काफी पहले घोषित किए जाते हैं ताकि किसान उसी के अनुसार अपनी फसल योजना बना सकें और अपनी कमाई को अधिकतम कर सकें।एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कुसुम के लिए घोषित की गई है, जो कि 600 रुपए प्रति क्विंटल है। इसके बाद मसूर (दाल) की एमएसपी में 300 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। रेपसीड और सरसों, चना, जौ और गेहूं के लिए, क्रमशः 250 रुपए प्रति क्विंटल, 225 रुपए प्रति क्विंटल, 170 रुपए प्रति क्विंटल और 160 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है।

भारत के पेंट उद्योग का आकार 2030 तक 16.5 अरब डॉलर पहुंचने का अनुमानः रिपोर्ट

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत का पेंट और कोटिंग्स उद्योग साल 2030 तक तेजी से बढ़ने वाला है। मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, इस उद्योग के हर साल लगभग 9.4 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ने का अनुमान है। साल 2024 में यह 9.6 अरब डॉलर था, जो अगले 5 वर्षों में बढ़कर 16.5 अरब डॉलर हो सकता है।

रुबिक्स डेटा साइंसेज (रुबिक्स) की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस उद्योग की बढ़त के कई कारण हैं। देश में तेजी से शहरीकरण, लोगों की आय में बढ़ोतरी, नई इमारतों व सड़कों का निर्माण और घरों की संख्या बढ़ना इसकी मुख्य वजहें हैं।

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है और सरकार इसे आने वाले 5 वर्षों में टॉप पर पहुंचाना चाहती है, जिससे कारों और फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाले पेंट और कोटिंग्स की मांग बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार, सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी और ग्रामीण) जैसी योजनाओं के कारण भी पेंट उद्योग को फायदा मिल रहा है। इन योजनाओं के तहत लाखों घर बनाए जा रहे हैं, जिससे पेंट की मांग बढ़ रही है।

हालांकि पेंट उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन वित्त वर्ष 2025 में इस क्षेत्र को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बड़ी पेंट कंपनियों का मुनाफा कम हुआ, शहरों में मांग थोड़ी धीमी रही और कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। देश में तकरीबन 3,000 छोटे और असंगठित पेंट कंपनियां हैं, जिन्हें सरकारी नियमों का पालन, नई तकनीक में निवेश और मार्केटिंग में दिक्कतें आईं, जिससे उनका बाजार में टिके रहना मुश्किल हो गया।

वहीं इस उद्योग में नई कंपनियों के आने से प्रतिस्पर्धा और बढ़ गई है। बड़ी कंपनियां आपस में मिलकर (विलय करके) और मजबूत बन रही हैं, जिससे छोटे खिलाड़ियों पर दबाव बढ़ रहा है। भारत ज्यादातर पेंट विकासशील देशों को निर्यात करता है, लेकिन उन्नत और खास तरह के पेंट और कच्चा माल (जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड) विकसित देशों से आयात करता है। वित्त वर्ष 2026 के पहले छह महीनों में भारत ने 219 मिलियन डॉलर का पेंट आयात किया, जबकि 61 मिलियन डॉलर का निर्यात हुआ।

समीरा रेड्डी ने शेयर की 'बनाना स्टेम' जूस की रेसिपी, बताया डिटॉक्स का प्राकृतिक तरीका

मुंबई। लंबे अंतराल के बाद अभिनेत्री समीरा रेड्डी फिल्म 'चिमनी' से बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। अभिनेत्री फिटनेस और हेल्दी डाइट को लेकर काफी एक्टिव रहती हैं। वे सोशल मीडिया पर अक्सर फिटनेस टिप्स, हेल्थ के लिए रेसिपी और प्राकृतिक उपाय शेयर करती रहती हैं। इसी का नमूना पेश करते हुए अभिनेत्री ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने केले के तने (बनाना स्टेम) का जूस पीने के फायदे के बारे में बताया। वीडियो में समीरा केले के कटे हुए तने को मिक्सर में डालकर जीरे के साथ पीसती हैं और छानकर ताजा जूस निकालकर पीती हैं।

वीडियो में अभिनेत्री कहती हैं कि पहले उन्हें पता नहीं था कि केले के तने के इतने सारे फायदे होते हैं। वीडियो शेयर कर अभिनेत्री ने इसके फायदे के बारे में बताते हुए लिखा, 'केले के तने का पानी शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है, साथ ही पेट की सूजन को कम करता है और पाचन को भी बेहतर बनाता है।'

अभिनेत्री ने आगे जूस की विधि बनाते हुए लिखा, 'इसको बनाने के लिए कटे हुए केले के तने के टुकड़ों को जीरे के साथ मिक्सर में डालें, अच्छी तरह पीस लें, फिर छानकर रस निकाल लें।'

उन्होंने आगे लिखा, 'केले के तने का जूस प्रकृति का असली इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक माना जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, पोटेशियम, विटामिन बी6, और आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। सुश्रुत संहिता में केले के तने को 'वज्राई थंडू' नाम से उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार, यह पाचन सुधारने, वजन घटाने, पथरी रोकने और एसिडिटी कम करने में बहुत फायदेमंद है। साथ ही, यह वात-पित्त दोषों को संतुलित करने में भी अहम भूमिका निभाता है और शरीर को ठंडक पहुंचाता है। गर्मियों में इसे जरूर पीना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है, जो शरीर के तापमान को संतुलित करती है।

सोनू सूद ने बताई 'चैरिटी फाउंडेशन' शुरू करने की वजह

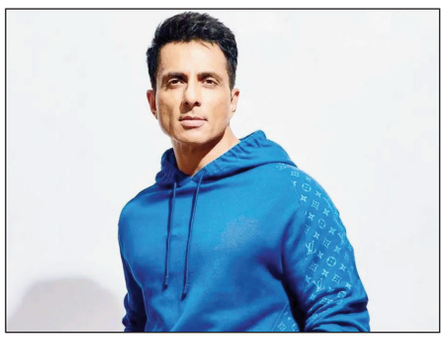

मुंबई। मशहूर अभिनेता सोनू सूद ने अपने करियर में ज्यादातर फिल्मों में विलेन का किरदार निभाया है, लेकिन असल जीवन में वे एक सच्चे हीरो से कम नहीं हैं। वे कोरोना के समय प्रवासी मजदूरों की मदद से लेकर पंजाब में बाढ़ प्रभावितों की सहायता करते नजर आए थे। अभिनेता ने सामाजिक कार्यों से समाजसेवा की एक नई मिसाल पेश की है। उन्होंने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन शुरू करने का उद्देश्य बताया।

अभिनेता का कहना है कि फाउंडेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत और यहां की महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर से मुक्त करवाना है। उन्होंने कहा, 'कई महिलाएं आर्थिक तंगी या सामाजिक कारणों से अस्पताल नहीं जा पातीं या फिर अपनी तकलीफें किसी से नहीं कह सकती हैं। हमारी इस पहल के तहत देश के किसी भी कोने में रहने वाली ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिलाओं की सर्जरी पूरी तरह मुफ्त में करवाई जाएगी।' अभिनेता ने बताया कि उनकी टीम ने 500 से ज्यादा सर्जरी सफलतापूर्वक करवाई हैं, जिससे इतने ही लोगों की जान बची हैं और 500 से अधिक परिवारों को नया जीवन मिला है।

अभिनेता ने अपनी टीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, 'मैं अपनी टीम और उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने पीड़ित महिलाओं के मामलों की जानकारी दी और उन्हें फाउंडेशन तक पहुंचाया।'उन्होंने आखिरी में कहा कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। उन्होंने कहा, 'मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि अगर कोई महिला ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित मिले, तो उन्हें हमारे पास लाएं। हम उनका इलाज एकदम मुफ्त में करवाएंगे। एक नया जीवन देंगे और साथ में मिलकर इस देश को और महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर से मुक्ति दिलवाएंगे और एक नया अध्याय लिखेंगे कि किस तरह हम मिलजुलकर लोगों की जान बचा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।' अभिनेता अक्सर जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहते हैं। उन्होंने साल 2020 में किसान की दो बेटियों की मदद की थी। दरअसल, सोशल मीडिया पर किसान की बेटियों का खेत जोतते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। सूद ने उस किसान परिवार को तुरंत एक ट्रैक्टर भिजवाया था।

'आवाज कहां तक जानी चाहिए?... लाहौर तक', 'बॉर्डर 2' का टीजर रिलीज

मुंबई। बॉलीवुड में देशभक्ति और एक्शन का जादू फिर से पर्दे पर लौटने को तैयार है। सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' का टीजर मंगलवार को आखिरकार रिलीज हो गया। यह टीजर दो मिनट चार सेकेंड का है। इसमें देशभक्ति की झलक को बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। टीजर की शुरुआत सनी देओल की दमदार आवाज के साथ होती है। वे जोश और जुनून से भरी आवाज में कहते हैं, 'तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, आसमान से, जमीन से, समंदर से सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे जो आंखों में आंखें डालकर कहेगा, 'हिम्मत है तो आगे आ, ये खड़ा है हिंदुस्तान।'

टीजर में भारत-पाक युद्ध 1971 की पृष्ठभूमि पर आधारित घटनाओं की झलक दिखाई गई है। शकरगढ़ सेक्टर में धमाके, श्रीनगर के आईएएफ बेस पर घायल जवान और उत्तरी अरब सागर में नेवी की कार्रवाई, यह सब टीजर में बेहद रोमांचक तरीके से पेश किया गया है।सनी देओल मिसाइल गन चलाते नजर आते हैं, वहीं वरुण धवन थल सेना के जवान के किरदार में दिखते हैं। दिलजीत दोसांझ वायु सेना के जवान के रूप में हैं और अहान शेट्टी नेवी के जवान के किरदार में हैं। हर सीन में भारतीय सेना की बहादुरी, जोश, और समर्पण साफ नजर आता है। एक सीन में जवानों का जोश हाई करते हुए सनी देओल कहते हैं, 'आवाज कहां तक जानी चाहिए?' इस पर सभी जवान एक साथ जोर से कहते हैं, 'लाहौर तक।'

टीजर में दमदार एक्शन के साथ-साथ फिल्म के प्रमुख किरदारों की बैकस्टोरी और उनके रिश्तों की झलक भी दिखाई गई है। सनी देओल के साथ मोना सिंह, दिलजीत दोसांझ के साथ सोनम बाजवा, वरुण धवन के साथ मेधा राणा और अहान शेट्टी के साथ आन्या सिंह नजर आए।

विदेश

ट्रंप ने फेंटेनाइल को 'सामूहिक विनाश का हथियार' घोषित किया

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करते हुए फेंटेनाइल को सामूहिक विनाश का हथियार घोषित किया है। उन्होंने कहा कि यह सिंथेटिक ओपियोइड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है।

पीएम मोदी का इथियोपिया दौरा हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धिः सुनील श्रीवास्तव

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इथियोपिया यात्रा को लेकर वहां रह रहे भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। पीएम मोदी 16 से 17 दिसंबर तक इथियोपिया के दौरे पर रहेंगे।

मजबूत होती साझेदारीः भारत-यूएई संयुक्त आयोग में एस. जयशंकर ने की द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा

अबू धाबी। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के साथ 16वीं संयुक्त आयोग बैठक और पांचवीं रणनीतिक वार्ता की सह-अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और यूएई के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा की और आने वाले समय की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की।मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि आज के समय में भारत और यूएई के बीच गहरा सहयोग साझा हितों को आगे बढ़ाता है और क्षेत्रीय व वैश्विक स्थिरता में योगदान देता है।

बैठक में विदेश मंत्री ने बताया कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते और द्विपक्षीय निवेश संधि के बाद भारत-यूएई के बीच व्यापार, निवेश, वित्तीय तकनीक और डिजिटल कनेक्टिविटी में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि पर प्रकाश डाला। उन्होंने कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में भी बड़ी संभावनाओं की ओर ध्यान दिलाया, जिसमें भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा जैसी पहलें शामिल हैं।

उन्होंने ऊर्जा सहयोग के विस्तार पर भी जोर दिया, खासतौर पर नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को मजबूत करने तथा रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और सुदृढ़ करने की बात कही। इसके अलावा, उन्होंने लोगों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने, महत्वपूर्ण खनिज, अंतरिक्ष और ध्रुवीय अनुसंधान जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आपसी समन्वय को अहम बताया।

सोमवार को विदेश मंत्री जयशंकर ने अबू धाबी में यूएई के उपराष्ट्रपति शेख मंसूर बिन जायद बिन सुल्तान अल नाहयान से भी मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक और रक्षा सहयोग को और आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई।जयशंकर ने 'एक्स' पर लिखा कि उपराष्ट्रपति से मुलाकात सम्मान की बात है और भारत-यूएई के बीच आर्थिक और रक्षा सहयोग को गहरा करने पर उपयोगी बातचीत हुई।

इसके अलावा, विदेश मंत्री ने यूएई की मुबाडाला निवेश कंपनी के प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी खलदून खलीफा अल मुबारक से भी मुलाकात की। इस बैठक में वैश्विक भू-आर्थिक परिदृश्य और भारत-यूएई संबंधों को और मजबूत करने के अवसरों पर विचार किया गया।जयशंकर ने बताया कि इस चर्चा में आर्थिक सहयोग की नई संभावनाओं पर भी बात हुई और दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने की जरूरत पर सहमति बनी।

दिल्ली में अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ सर्विस सेक्टर में सहयोग पर होगी चर्चा

नई दिल्ली। अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मौलवी नूर जलाल जलाली मंगलवार को भारत पहुंचे। यह उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए चर्चा करना है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री की भारत यात्रा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के पब्लिक हेल्थ मंत्री मौलवी नूर जलाल जलाली का भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर हार्दिक स्वागत है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह यात्रा अफगानिस्तान के हेल्थकेयर सिस्टम के लिए भारत के लगातार समर्थन को दिखाती है, और हम उपयोगी बातचीत की उम्मीद करते हैं। भारत ने अफगानिस्तान के स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में योगदान दिया है, जो अफगान लोगों के प्रति उसके अटूट समर्थन की पुष्टि करता है।इस महीने की शुरुआत में भारत ने काबुल को इन्फ्लूएंजा और मेनिन्जाइटिस के टीकों की 63,734 खुराकें भेजीं।

28 नवंबर, भारत ने अफगानिस्तान को स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए 73 टन जीवन रक्षक दवाएं, टीके और आवश्यक पूरक सामग्री भेजीं। विदेश मंत्रालय ने 'एक्स' पोस्ट कर कहा, 'अफगानिस्तान के स्वास्थ्य सेवा प्रयासों को बढ़ावा देते हुए भारत ने तत्काल चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काबुल को 73 टन जीवन रक्षक दवाएं, टीके और आवश्यक पूरक सामग्री भेजी हैं। अफगान जनता के प्रति भारत का अटूट समर्थन जारी है।'

विजय दिवस पर शेख हसीना की चेतावनीः '1971' में पराजित हुई ताकतों का फिर से हो रहा उभार

ढाका। बांग्लादेश के विजय दिवस के अवसर पर देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चिंता जताई है कि वर्ष 1971 के मुक्ति संग्राम में पराजित हुई ताकतें फिर से सक्रिय हो गई हैं। यह वही युद्ध था, जिसमें बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ आजादी हासिल की थी। शेख हसीना ने याद दिलाया कि अवामी लीग के नेतृत्व में नौ महीने तक चले संघर्ष के बाद 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को बड़े बलिदानों के साथ जीत मिली थी और पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा था।

पूर्व पीएम द्वारा जारी बयान को अवामी लीग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया गया। बयान में कहा गया, 'जीत के गौरव के साथ, आज दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि 1971 की हारी हुई ताकतें एक बार फिर उठ खड़ी हुई हैं। भेदभाव विरोधी आंदोलन की आड़ में लोगों को धोखा दिया गया, योजनाबद्ध हिंसा फैलाई गई और अवैध तरीके से सत्ता पर कब्जा किया गया।'

शेख हसीना ने कहा कि वर्ष 2024 में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान सबसे पहला हमला बंगबंधु के घर धनमंडी 32 पर हुआ। यही वह ऐतिहासिक स्थान है, जहां से बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा की गई थी। इसके बाद पूरे देश में मुक्ति संग्राम से जुड़े स्मारकों पर हमले किए गए।उन्होंने कहा, ₹5 अगस्त को, पहला हमला खुद बंगबंधु पर किया गया। धनमंडी 32 में ऐतिहासिक घर, जो बंगाली स्वतंत्रता संघर्ष और मुक्ति संग्राम की यादों से गहराई से जुड़ा हुआ है।

जापान के रक्षा मंत्री बोले,' चीन-रूस बॉम्बर विमानों की संयुक्त उड़ानें धमकी समान'

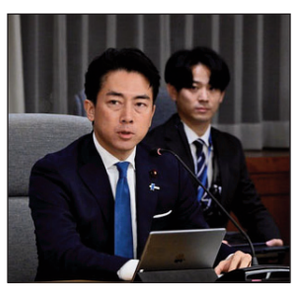

टोक्यो। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी ने मंगलवार को पश्चिमी जापान के शिकोकू क्षेत्र के पास चीन और रूस की संयुक्त बॉम्बर उड़ान पर अपनी चिंता व्यक्त की और इसे शक्ति का प्रदर्शन बताया। स्थानीय मीडिया ने उनके बयान के हवाले से ये जानकारी दी है।

जापान टुडे के अनुसार, कोइज़ुमी ने इस मामले को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब सीधे तौर पर नहीं दिया, लेकिन पत्रकारों से कहा, 'मैं चीन और रूस के इरादों के बारे में पक्का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन कह सकता हूं कि उनकी बार-बार होने वाली ज्वाइंट बॉम्बर उड़ानें जापान के आसपास उनकी गतिविधियों के विस्तार को दर्शाती हैं। इन हरकतों को धमकी के तौर पर देखा जाना चाहिए।'

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, संयुक्त अभ्यास के दौरान दो रूसी टीयू-95 बॉम्बर जापान सागर से उड़े और पूर्वी चीन सागर के ऊपर दो चीनी एच-6 बॉम्बर से मिले, जिसके बाद वे 9 दिसंबर को शिकोकू के मुख्य द्वीप के पास प्रशांत महासागर की ओर बढ़ गए।

कोइज़ुमी ने कहा कि यह नवंबर 2024 के बाद दोनों देशों की पहली ज्वाइंट बॉम्बर उड़ान थी और कुल मिलाकर नौवीं थी। उन्होंने कहा कि इस कदम से जापान को संभावित एयरस्पेस उल्लंघन को रोकने के लिए फाइटर जेट भेजने पड़े, और यह भी कहा कि यह चीन और रूस की शिकोकू (द्वीप) के पास आने वाली पहली ज्वाइंट बॉम्बर उड़ान थी।कोइज़ुमी ने कहा कि रक्षा मंत्रालय और सेल्फ-डिफेंस फोर्सेस शांत और दृढ़ तरीके से जवाब देते हुए सतर्कता और निगरानी बनाए रखेंगी।

उन्होंने यह भी दोहराया कि 6 दिसंबर को जापान के ओकिनावा प्रांत के पास एक चीनी जे-15 विमान द्वारा एयर सेल्फ-डिफेंस फोर्स के एफ-15 पर लगभग 30 मिनट तक रडार लॉक करना एक ₹खतरनाक हरकत₹ थी।चीन की नौसेना के लड़ाकू विमानों ने 6 दिसंबर को ओकिनावा के दक्षिण-पूर्व में जापानी एफ-15 जेट्स पर दो बार फायर-कंट्रोल रडार लॉक किया था, जिसे लेकर जापान ने आपत्ति जताई थी।9 दिसंबर के रूस-चीन के संयुक्त अभ्यास के बाद अमेरिका और जापान ने भी पैसिफिक में ज्वाइंट ड्रिल की थी।